कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qksu (dk-) : +91(11) 23381428

QSDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

भारत–जापान संबंध

ऐतिहासिक रही प्रधानमंत्री की जापान यात्रा.. 7

भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंध

असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग करार एक ऐतिहासिक कदम..................... 17

लेख

मोदी सरकार के 100 दिनों की सफलता अभूतपूर्व रही है
– **सारस्वत पाणिग्रही**.. 26

पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितम्बर पर विशेष

एक मानव तनधारी देवदूत
–**के आर मल्कानी**.. 28

अन्य

प्रधान मंत्री जन धन योजना का शुभारंभ.. 19

शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री ने छात्रों से बातचीत की............................ 21

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास.. 22

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं!

बोध कथा

दो पैसे का मेला

यह घटना सन 1942 की है। उन दिनों इलाहाबाद में कुंभ के मेले की धूम मची हुई थी। भारत के वायसराय उन दिनों लार्ड लिनलिथगो थे। वह भी कुंभ का मेला देखने के लिए पंडित मदनमोहन मालवीय जी के साथ इलाहाबाद पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुंभ में देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जातियों और समूहों के लोग विभिन्न वेशभूषाओं में सजकर आए हुए हैं। यह सब देखकर वायसराय हैरान हुए और मालवीय जी से पूछा, 'इस मेले में लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रचार-प्रसार पर तो काफी रुपया खर्च होता होगा! कुछ अनुमान है कि कितना रुपया लग जाता है?'

वायसराय की यह बात सुनकर मालवीय जी मुस्कराते हुए बोले, 'मात्र दो पैसे।' यह सुनकर वायसराय दंग रह गए और बोले, 'क्या कहा आपने? मात्र दो पैसे? भला यह कैसे संभव है? भला दो पैसे से यहां इतनी भीड़ कैसे जुटाई जा सकती है?' वायसराय की बात सुनकर मालवीय जी ने अपने पास से पंचांग निकाला और उसे दिखाते हुए बोले, 'इस दो पैसे के पंचांग से देश भर के श्रद्धालु यह पता लगते ही कि कौन सा पर्व कब है, स्वयं श्रद्धा के वशीभूत होकर तीर्थयात्रा को निकल पड़ते हैं। धार्मिक संस्थाओं व सभाओं को कभी भी न प्रचार की आवश्यकता पड़ती है और न ही इन लोगों को निमंत्रण भेजने की।' मालवीय जी की बात सुनकर वायसराय को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, 'वाकई यह तो बड़े अचरज की बात है।' मालवीय जी उनकी बात का जवाब देते हुए बोले, 'अचरज की बात नहीं जनाब, यह मेला श्रद्धालुओं का अनूठा संगम है। यहां सब अपने आप खिंचे चले आते हैं।' वायसराय श्रद्धालुओं के प्रति नतमस्तक हो गए।

संकलन : जयगोपाल शर्मा

(नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय...

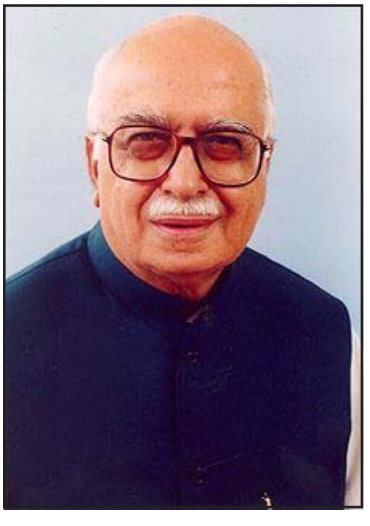

"भारतीय राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणाओं में निहित अनंत शक्ति को मान्य करके ही अलगाववादी ताकतें खत्म कर राष्ट्र को एकजुट किया जा सकता है। यह बात गौण है कि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इस अवधारणा को कैसे बताते हैं- हिन्दुत्व के रूप में या भारतीयता के रूप में। मूल तत्व तो एक ही है।"

- लालकृष्ण आडवाणी

जन-जन की ओर बढ़ रही मोदी सरकार

सौ दिन बीत गए। देशवासी, भारत की प्रगति और विकास की रफ्तार देख रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि भारत की साख बढ़ेगी। पर विपक्षी खासकर कांग्रेसी अपनी पीत निगाहों से ही वर्तमान भाजपा-नीत एनडीए सरकार को देख रही है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेसी हैरान है। सपा परेशान है। लालू अस्पताल में हैं। मायावती और नीतीश कुमार साम्प्रदायिकता का रोना रो रहे हैं। अभी तक इन विपक्षियों को लग रहा था कि 'ये क्या चला पायेंगे' लेकिन अब विपक्षी स्वयं हतप्रभ हैं। वास्तविकता भी यही है कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों और सांसदों ने विकास की सकारात्मक धारा को पकड़ लिया। मौलिक चिंतन और मूल सामाजिक समस्याओं की ओर भाजपानीत एनडीए सरकार आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शपथ समारोह से लेकर 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन तक हर दिन का हर मिनट राष्ट्र के लिए उपयोग किया। सौ दिन के भीतर सबसे बड़ी बात हुई है कि भारतीय राजनीति, राजनीतिज्ञों और राजनैतिक दलों की जो साख डूब रही थी उस पर विराम ही नहीं लगा बल्कि भारतवासियों का विश्वास पुनः लौटने लगा है। निराश, हताश और संत्रास में जी रहे भारतीयों की सोच में अंतर आया। खोया हुआ जनविश्वास लौट आया है। जनतंत्र में जनविश्वास की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ 26 मई को और 27 मई से भाजपा नीत सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। कालेधन की वापसी के लिए एसआईटी का गठन कर देश को विश्वास दिलाया कि अब कालेधन से हर तरह का पर्दा उठ जाएगा।

मोदी सरकार ने शपथ समारोह में ही यह संदेश दिया कि हम अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध रखना चाहते हैं। उसकी शुरुआत उन्होंने भूटान और नेपाल से की। पाकिस्तान की ओर भी वार्ता के आधार पर बढ़े। परन्तु पाकिस्तान ने अलगाववादियों से चर्चा की तो भारत ने कहा अब वार्ता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हम किसी को आंखें नहीं दिखाएंगे और न झुकाएंगे बल्कि आंखें मिलाकर बात करेंगे। पाकिस्तान को पहली बार लगा कि अब पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। भारत से वार्ता होगी तो सिर्फ भारत से न कि अलगाववादियों से। पाकिस्तान सरहद पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि घात करोगे तो बात नहीं होगी। इन घटनाओं से भारत का स्वाभिमान बढ़ा है।

कांग्रेसाध्यक्षा अभी तक महंगाई को रो रही हैं। उन्हें पता ही नहीं कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए पूरा मंत्रिमंडल प्रतिबद्ध है। हम पूछना चाहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी से कि क्या आलू-प्याज के दाम नियंत्रित नहीं हैं? गेहूं-चावल, आटा, तेल और दलहन के दाम क्या बढ़े हैं? क्या टमाटर के दाम नियंत्रित नहीं हुए? देश में महंगाई नियंत्रित हुई है। दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम एक महीने में दो बार कम नहीं हुए हैं क्या? पहली बार दो रुपए छियासी पैसे। दूसरी बार पुनः पेट्रोल के दाम एक रुपए बयासी पैसे कम हुए। एक माह में पौने पांच रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम होना क्या भाजपानीत एनडीए की उपलब्धि नहीं है। एलपीजी गैस सिलेण्डर की कीमत उन्नीस रुपए प्रति सिलेण्डर कम होना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। इन मसलों पर सोनियाजी और उनकी पार्टी क्या कहेंगी? देश में सच्चा और अच्छा विपक्ष होता तो वह जापान में फोन लगाकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनकी सफलतम, यात्रा जो अभी चल ही रही थी, पर बधाई देता। काश! विपक्षी दल ऐसा कर पाते। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि श्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के नहीं बल्कि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं।

भारत की सीमा, संसद, संविधान और सेना का स्वाभिमान नहीं गिरे, इस ओर भी नरेन्द्र मोदी ने ध्यान दिया है। आज भारत का सामान्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री को mygov.nic.in पर सुझाव दे सकता

है। भारत सबका है।

कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी। उसने अपने कार्यकाल में गंगा मैली की और सफाई के नाम पर जो पैसे आए, वह कहां गए, आज तक पता नहीं। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि मुझे मां, गंगा ने बुलाया है। उसके बाद गंगा सफाई की एक कार्ययोजना बनी। पांच मंत्रालयों को इस काम पर लगाया। कोई सोचता था कि स्मार्ट सिटी योजना बने पर नरेन्द्र मोदी ने इसे साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। सचिवालयों और सरकारी महकमों की कार्यपद्धति में बदलाव आया है। स्वच्छता अभियान पर जोर दिया गया है। सफाई की ओर विशेष ध्यान देने की केवल बात नहीं कही गई बल्कि इसकी शुरुआत की गई। 2 अक्तूबर गांधी जयंती से भारत में स्वच्छता अभियान की शुरूआत करने की घोषणा कांग्रेसियों को पच नहीं रही। 68वीं वर्षगांठ पर लालकिले की प्राचीर से देश के महिला स्कूलों में, कॉलेजों में और वैसे भी शौचालयों की समस्या और उसके निदान के लिए रास्ता निकालने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने देश के सामाजिक दर्द को छूने का प्रयास किया।

भारत की आधी आबादी (लड़कियां-बालिकाएं) उन पर विशेष ध्यान देने की घोषणा भारतीय संस्कार से जुड़ी हुई हैं। गुजरात के सफल प्रशासक रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को भी कुशल रूप से चलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के सवा सौ करोड़ नागरिक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश सवा सौ करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। विकास में सभी का सहयोग चाहिए। उन्होंने देश के विपक्ष से भी अपील की कि वे भी विकास में साथ आएं।

बोझ बन चुका योजना आयोग को समाप्त कर वर्तमान में उसके नए स्वरूप में लाने के निर्णय को देश ने सराहा है।

जन-धन योजना से देश के गरीबों ने अपना खाता बैंक में खोलकर उस पंक्ति में खड़ा करने की कोशिश की है, जहां वे वर्षों से नहीं आ पा रहे थे। नरेन्द्र मोदी ने भारत के मन-आत्मा और उसके मूल प्रकृति को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। वे देश के बदहाल गरीबों की तकदीर बदलना चाहते हैं। जन-धन योजना उसी दिशा में एक कारगर कदम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा की घोषणा की गई। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के प्लेटफार्म के जरिए शिक्षा और टेलिमेडिसीन सुविधाएं भी देने की बात कही गई है। जजों की नियुक्ति के लिए बीस साल से जो विधेयक कांग्रेस नहीं ला पा रही थी उसे मोदी सरकार दो दिन के भीतर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। रेलवे और रक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर एफडीआई का फैसला भी ऐतिहासिक है।

भारत में तीर्थयात्रा और पर्यटन पर जोर देने का प्रयास किया। रेल बजट में जो-जो घोषणाएं की गई, वह साकार होने लगीं। बजट में कही गई सत्तावन नई रेल एक सितंबर से शुरू हो गई।

नरेन्द्र मोदी की सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती बल्कि उसे साकार करती है। भारत ने डब्ल्यूटीओ का लंबे समय से लंबित ग्लोबल ट्रेड पैक्ट साइन करने से मना कर दिया। फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक स्टाक होल्डिंग पर किसी समाधान के बिना भारत इस पैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था।

ब्रिक्स दौरे में सफल भूमिका रही। स्वयं मोदी छाये रहे। ब्रिक्स के पांचों देशों ने ब्रिक्स बैंक को चीन के शंघाई शहर में बनाने की बात तय हुई तो यह भी तय हुआ कि इसका पहला प्रमुख भारत का होगा।

इराक संकट में विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने जिस बुद्धिमता का परिचय दिया, वह देश ने अपनी आंखों से देखा। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भारतीयों को जिस तरह छुड़ाया गया, उसकी सारे देश ने प्रशंसा की।

भारत के वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने जब आम बजट देश के सामने रखा तो पहली बार देशवासियों ने अपने को आम-बजट में पाया। गरीब, अमीर, युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित उद्योगपति सभी के लिए आम बजट। देश ने अरुण जेटली की पीठ थपथपाई। आम बजट भारत के आम नागरिकों के लिए था। समाचार माध्यमों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

सौ दिन के निर्णय अगर लिखें तो बहुत लिखना पड़ेगा। किसी सरकार के लिए सौ दिन सामान्य होते हैं। पर इसी सौ दिन में देश के मानस को जीतना सामान्य बात नहीं थी। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सौ दिन में भाजपानीत एनडीए सरकार ने जो जनविश्वास जीता है, वह असामान्य है। पहले की सरकारें देश से कटी होती थीं और जनता भी उनसे पूरी तरह कटी रहती है। पर मोदी सरकार की सफलता यही है कि वह पूरी तरह जनता से जुड़ी है और जनता भी पूरी तरह अपनी सरकार से जुड़ी है। आज देश की जनता को मोदी सरकार पर गौरव हो रहा है। उन्हें लग रहा है, हमने जिसे चुना वह हमारे पैमाने पर खरा उतर रहा है। जो सरकार जनता की आत्मा से जुड़ जाए, वह जन-जन की सरकार होती है। मोदी सरकार धीरे-धीरे जन-जन की सरकार बन रही है। ■

ऐतिहासिक रही प्रधानमंत्री की जापान यात्रा

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 30 अगस्त से 3 सितंबर तक की जापान यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री तथा जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौजूदगी में वाराणसी-क्योतो साझेदार शहर संबद्धता समझौते पर हस्ताक्षर हुए। क्योतो के शाही अतिथि गृह की भव्यता के बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने मेजबान जापान के प्रधानमंत्री श्री आबे के साथ डेढ घंटे से अधिक समय तक भोज की मेज पर परंपरागत जापानी भोज के साथ मैत्रीपूर्ण वार्ता के लिए बैठे। श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ क्योतो में प्राचीन तोजी मंदिर के दर्शन किए और गोल्डन पैविलियन में किंकाजू-जी मंदिर की यात्रा की। श्री मोदी ने ताइमेई एलिमेन्ट्री स्कूल का दौरा किया। जापान के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर एवं जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति-निप्पॉन किडनरेन द्वारा आयोजित दोपहर के भोज पर प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। टोक्यो में भारतीय समुदाय के समारोह को श्री मोदी ने संबोधित किया। श्री मोदी ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया।

हम यहां ''तथ्य पत्र : भारत और जापान - साझा विकास के लिए भागीदार'' और ''भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी के लिए टोक्यो घोषणा-पत्र'' का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी के लिए टोक्यो घोषणा-पत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 1 सितंबर, 2014 को टोक्यो में अपनी बैठक के दौरान अपने देश की आम जनता की तरक्की एवं समृद्धि को सतत् रूप से जारी रखने और एशिया तथा विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत-जापान सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी का पूर्ण इस्तेमाल करने का संकल्प व्यक्त किया। आपसी रिश्तों को एक विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी के मुकाम पर पहुंचाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी इस बैठक से भारत-जापान संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

प्रधानमंत्री आबे ने भारत से बाहर अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा

के लिए जापान का चयन करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनके इस निर्णय से भारत की विदेश नीति एवं आर्थिक विकास में जापान की अहमियत और भारत की 'पूरब की ओर देखो' नीति में जापान के खास स्थान की झलक मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-जापान सामरिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर गहरी प्रतिबद्धता दिखाने, गर्मजोशी के साथ अपनी अगवानी किए जाने और टोक्यो में आज संपन्न चर्चा के दौरान साहसिक दृष्टिकोण पेश करने के लिए प्रधानमंत्री आबे को धन्यवाद कहा।

दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने यह बात रेखांकित की कि भारत और जापान एशिया के दो सबसे बड़े एवं सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश हैं तथा दोनों देशों के लोगों के बीच प्राचीन समय से ही सांस्कृतिक संपर्क एवं सद्भाव बरकरार रहे हैं। आपस में जुड़ते वैश्विक हितों, महत्वपूर्ण नौवहन अंतर-संपर्क और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों ने भी इन दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब ला दिया है। दोनों देश शांति व स्थिरता, कानून के अंतर्राष्ट्रीय नियम और खुली वैश्विक व्यापार व्यवस्था के प्रति कटिबद्ध हैं। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कई चीजें एक-दूसरे की पूरक हैं, जिससे आपसी लाभप्रद आर्थिक भागीदारी के असीम अवसर नजर आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे ने कहा कि भारत और जापान के आपसी रिश्ते- इसलिए भी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के तमाम राजनीतिक दल, कारोबारी समुदाय और वहां की आम जनता इस संबंध की अहमियत एवं संभावनाओं को बखूबी समझती है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने फैक्ट शीट में उल्लेखित सहयोग कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में हुई प्रगति का स्वांगत किया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा में आपसी सहमति से और ज्यादा प्रगति सुनिश्चित की जाए।

सियासी, रक्षा व सुरक्षा भागीदारी

दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय बैठकों के साथ-साथ वार्षिक शिखर बैठकों की परंपरा जारी रखने और कम अंतराल पर ज्यादा से ज्यादा बैठकें आयोजित करने का फैसला किया।

बहु-क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय और कैबिनेट स्तर की बातचीत खासकर विदेश मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों तथा वित्त, आर्थिक, व्यापार व ऊर्जा मंत्रियों के बीच वार्ताओं के जरिए भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय भागीदारी की विशेष गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस तरह के आदान-प्रदान को नई गति प्रदान करने का फैसला किया। इस संदर्भ में उन्होंने इस सूचना का स्वागत किया कि विदेश मंत्रियों के बीच सामरिक वार्ता और रक्षा मंत्रियों के बीच सामरिक वार्ता वर्ष 2014 में ही आयोजित की जानी है। उन्होंने जापान में राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय, जिसे तमाम सुरक्षा मसलों पर आपसी सहमति व सहयोग को बढ़ाने में काफी सहायक माना जा रहा है, के सृजन के तुरंत बाद इस साल के आरंभ में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई बैठक को काफी अहम बताया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपसी सामरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विदेश व रक्षा सचिवों को शामिल करते हुए '22 वार्ता' की अहमियत रेखांकित की। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने इस तरह की वार्ताओं में और तेजी लाने का फैसला किया है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी सामरिक भागीदारी के तहत भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों की अहमियत की फिर से पुष्टि करते हुए इसमें और मजबूती लाने का फैसला किया है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग और आदान-प्रदान के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। इस संदर्भ में उन्होंने द्विपक्षीय नौवहन अभ्यासों को नियमित रूप से जारी रखने और भारत-अमेरिका मालाबार अभ्यासस शृंखला में जापान की निरंतर भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने आपसी बातचीत के मौजूदा स्वरूप और भारत तथा जापान के कोस्ट गार्डों के बीच संयुक्त अभ्यास का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जुड़ी जापानी नीति में हाल में हुए बदलावों का स्वागत किया। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने उम्मीद जतायी है कि इससे रक्षा उपकरणों

और प्रौद्योगिकी में सहयोग का एक नया युग शुरू होगा। उन्होंने यह माना कि भविष्य में दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और सहयोग की भरपूर गुंजाइश है। उन्होंने हवा और पानी दोनों में विचरण करने वाले यूएस-2 विमान एवं उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग पर संयुक्त कार्यदल बनाने की दिशा में हो रही चर्चाओं का स्वागत किया। उन्हों ने अपने अधिकारियों को इन चर्चाओं में तेजी लाने के निर्देश दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों को रक्षा उपकरण एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच कारगर सलाह-मशविरा शुरू करने का भी निर्देश दिया।

दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने नौवहन सुरक्षा और साइबर क्षेत्र में अपने व्यापक साझा हितों पर चर्चा की। उन्होंने इन वैश्विक साझा लक्ष्यों को पाने और अखंडता की रक्षा के लिए एक-दूसरे के अलावा समान सोच वाले भागीदारों के साथ भी काम करने का फैसला किया। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, नौ-परिवहन व ओवरलाइट की आजादी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा, बेरोकटोक वैधानिक वाणिज्य के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने को लेकर अपनी साझा प्रतिबद्धता फिर से दोहराई।

क्षेत्र एवं विश्व में शांति तथा सुरक्षा के लिए वैश्विक साझेदारी

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने साझे विश्वास के प्रति संकल्प व्यक्त किया कि ऐसे समय में जब दुनिया में अराजकता, तनाव और अशांति का दौर बढ़ रहा है भारत और जापान के बीच एक घनिष्ठ और मजबूत सामरिक साझेदारी दोनों देशों के समृद्ध भविष्य और विश्व में खासकर परस्पर संबद्ध एशिया, प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए अपरिहार्य है। प्रधानमंत्री आबे ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को 'शांति के प्रति अति सक्रिय योगदान' की जापानी नीति और समेकित सुरक्षा कानून के विकास पर जापान के मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने क्षेत्र और विश्व की शांति और सुरक्षा में जापान के योगदान का समर्थन किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने खासकर दोनों देशों के आपसी मूल्यों, विविध हितों और पूरक कौशलों तथा संसाधनों की ताकत का उपयोग अन्य इच्छुक देशों तथा क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास, क्षमता निर्माण तथा ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत साझेदारी करने का फैसला किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने, क्षेत्रीय सहयोग और एकता को मजबूत करने, क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा मंचों को ताकतवर बनाने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों तथा दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के अपने इरादे के प्रति संकल्प दोहराया। उन्होंने पूर्वी एशिया सम्मेलन प्रक्रियाओं तथा मंचों समेत क्षेत्रीय फोरमों में भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सलाह-मशविरे तथा समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने भारत, जापान और अमेरिका के बीच आधिकारिक त्रि-स्तरीय बातचीत में हुई प्रगति पर संतोष जाहिर किया और उम्मीद जताई कि इससे उनके आपसी तथा अन्य साझेदारों के हितों को आगे बढ़ाने में ठोस मदद मिलेगी। उन्होंने अपने विदेश मंत्रियों के बीच इस बातचीत के आयोजन की संभावना ढूंढने का फैसला किया। वे इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ किसी उपयुक्त समय पर अपने सलाह-मशविरे को विस्तारित करने की संभावना की भी तलाश करेंगे।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों एवं प्रकारों, चाहे उसका सूत्रधार, उद्भव या मकसद कुछ भी हो, की निंदा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के उभरते चरित्र को देखते हुए इससे निपटने के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की जरूरत है जिसमें जानकारियों और खुफिया सूचनाओं का ज्यादा आदान-प्रदान शामिल है। उन्होंने विभिन्न देशों में गिरती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई और आतंकवादियों के खुफिया अड्डों और ढांचों को खत्म करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद पर बहुस्तरीय कार्रवाई को फिर से पुनर्जीवित करने की अपील की जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना तथा अपनाया जाना शामिल है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने उत्तर कोरिया के नाभिकीय अस्त्रों तथा उसकी यूरेनियम समृद्धि गतिविधियों समेत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों के अनवरत विकास पर चिंता जताई। उन्होंने उत्तर कोरिया से गैर नाभिकीयकरण और इसकी अतंर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का पूरी तरह अनुपालन करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सभी महत्वपूर्ण समझौतों और '2005 छह पार्टी वार्ता संयुक्त वक्तव्य' के तहत इसकी प्रतिबद्धताओं समेत अन्य लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने उत्तर कोरिया से जल्द से जल्द अपहरण मुद्दों समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मानवीय चिंताओं पर भी ध्यान देने का आग्रह किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक स्थिर और शांतिपूर्ण मध्य-पूर्व, पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा समेत अपने आपसी हितों पर जोर दिया। उन्होंने संघर्ष के विभिन्न स्रोतों से क्षेत्र में जारी अराजकता और अस्थिरता पर गहरी चिंता जताई जिसका देशों और क्षेत्र के लोगों पर दुखद और विनाशकारी असर पड़ा था। उन्होंने माना कि क्षेत्र के संघर्षों को खत्म करना, आतंकवाद से मुकाबला करना और लम्बित मुद्दों का समाधान करना न केवल क्षेत्र के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ईरान के नाभिकीय मुद्दे पर पीड़ा और ईरान के बीच बातचीत का स्वागत किया और सभी पक्षों से राजनीतिक इच्छा दिखाने और मतभेद समाप्त करने की अपील की।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने आपसी संकल्प को दुहराया और

अफगानिस्तान में अफगानों की अगुवाई में 2014 के बाद भी आर्थिक विकास, राजनीतिक बहुवाद और सुरक्षा में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बनाए रखने की अपील की जिससे कि इसे एक अविभाजित, स्वतंत्र, संप्रभु, स्थिर और आतंकवाद, उग्रवाद और बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त एक लोकतांत्रिक देश बनने में मदद मिले।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार, खासकर स्थाई एवं अस्थाई दोनों वर्गों में इसके विस्तार, जिससे कि यह ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण, वैधानिक, कारगर और 21वीं सदी की वास्तविकताओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील बने, के लिए तात्कालिक जरूरत पर बल दिया। उन्होंने 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह तक इस दिशा में ठोस परिणाम की अपील की तथा इसे प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय रूप से तथा जी-4 के तहत अपने प्रयासों को बढ़ाने का फैसला किया। इस दिशा में उन्होंने अपने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने तथा अन्य सदस्य देशों तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने जुलाई 2014 में टोक्यो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ मुद्दों पर भारत-जापान सलाह-मशविरे के तीसरे दौर के परिणाम को भी रेखांकित किया।

असैन्य परमाणु ऊर्जा, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण

भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच असैन्य् परमाणु सहयोग की महत्ता पर दृढ़ता व्यक्त की और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौते पर बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। दोनों ने अपने अधिकारियों को बातचीत में तेजी लाने और जल्द समझौते तक पहुंचने तथा दोनों देशों में परमाणु अप्रसार व परमाणु सुरक्षा के मद्देनजर सहयोग के लिए निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने परमाणु अप्रसार में भारत के प्रयास की सराहना की। श्री आबे ने भारत द्वारा जापान से आने वाली तकनीक और वस्तुओं का इस्तेमाल जन विनाशक हथियारों (डब्लूएमडी) के निर्माण और इसकी व्यवस्था का हिस्सेदार नहीं बनने के दृढ़ आश्वासन की भी प्रशंसा की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जापान सरकार के उस फैसले की प्रशंसा की जिसमें भारत के 6 अंतरिक्ष और रक्षा संबंधित उद्यमों को जापान के फॉरेन इंड यूजर लिस्ट से हटाये जाने की बात कही गई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने उच्च तकनीकी और व्यापार में सहयोग को आगे बढ़ाये जाने की संभावनाओं पर विचार किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से चार अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रक व्यवस्थाओं में भारत को पूर्ण सदस्य बनाए जाने के लिए मिलकर काम करने की वचनबद्धता पर अपनी दृढ़ता जाहिर की। इन चार क्षेत्रों में परमाणु आपूर्ति समूह, मिसाइल नियंत्रण तकनीक प्रणाली, वासेनार समझौता और आस्ट्रेलिया समूह शामिल हैं।

समृद्धि के लिए सहयोग

जापान के प्रधानमंत्री श्री आबे ने भारत में खासकर बुनियादी ढांचा एवं विनिर्माण क्षेत्र में समावेशी विकास को तेज करने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी की साहसिक और महत्वाकांक्षी दृष्टि के लिए व्यापक तथा मजबूत जापानी भागीदारी को लेकर हामी भर दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के आर्थिक विकास में जापान की ओर से निरंतर समर्थन दिए जाने पर उसकी काफी प्रशंसा की है और कहा है कि जापान के अलावा किसी दूसरे देश ने भारत के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में इतना सहयोग नहीं दिया है।

दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने भारत-जापान निवेश संवर्धन भागीदारी की घोषणा की है जिसके तहत निम्न बिन्दु शामिल हैं :

(अ) दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने भारत में पांच वर्षों में जापान के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य संयुक्त रूप से हासिल करने का फैसला किया है। साथ ही दोनों देशों ने साथ मिलकर द्विपक्षीय व्यापार रिश्ते को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया है।

(ब) जापान के प्रधानमंत्री श्री आबे ने अगले पांच वर्षों में जापान की ओर से भारत में 3.5 ट्रिलियन येन का सार्वजनिक और निजी निवेश तथा वित्त पोषण करने का इरादा जताया है। इसमें विदेशों में विकास सहायता (ओडीए), सार्वजनिक एवं निजी परियोजनाओं के लिए उचित आर्थिक मदद मुहैया कराना शामिल है जिनमें दोनों देशों के साझा हित हैं। इन अगली पीढ़ी की परियोजनाओं में, बुनियादी ढांचा, संपर्क, परिवहन प्रणाली, स्मार्ट सिटी, गंगा के अलावा अन्य नदियों का कायाकल्प, उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास, जल सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग, कृषि शीत श्रृंखला और ग्रामीण विकास शामिल हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री आबे ने भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ओडीए के अंतर्गत इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को 50 अरब येन का ऋण देने को कहा है।

(स) दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना को लेकर दोनों देशों के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी की शुरुआत किए जाने का स्वागत किया है। साथ ही दोनों ने ''जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप'' और अन्य इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का साझा इरादा जाहिर किया है जो कंपनियों के लिए निवेश प्रोत्साहन का काम करेगा। इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) के रूप में प्रचलित नीति से कमतर नहीं आंका जाएगा।

(द) दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने अपने अधिकारियों को संयुक्त वित्त पोषण तंत्र तैयार करने का आदेश दिया है जिसके तहत सार्वजनिक-निजी साझेदारी, सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए शर्तें, परियोजना की प्रकृति, विकास की प्राथमिकताएं, खरीदारी की

नीतियां, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षमता का स्तर और स्थानीय स्तर पर मौजूद कौशल का इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने भारत में उचित बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में जापानी और भारतीय भागीदारी बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने का भी फैसला किया है।

(ड़) प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कर, प्रशासन और वित्तीय नियमन तथा निवेश को बढ़ावा देकर भारत में व्यापार माहौल को सुधारने को लेकर अपनी दृढ़ता को रेखांकित किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आगे द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री आबे ने मिझुहो बैंक की अहमदाबाद शाखा को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है।

पूर्वोत्तर भारत में विकास और संपर्क बढ़ाने और इस क्षेत्र को शेष भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक गलियारों से जोड़ने के लिए जापान के सहयोग पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने विशेष जोर दिया। इन प्रयासों को इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे को स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सिटी, जिसमें कि वाराणसी भी शामिल है, का कायाकल्प करने के बारे में अपने प्रयासों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री श्री आबे ने उनके इस उद्देश्य में जापान द्वारा सहयोग देने की इच्छा जाहिर की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्राचीन शहर वाराणसी और क्योतो के बीच सहयोग समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री श्री आबे ने भारत में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास व हाई स्पीड रेलवे प्रणाली को लेकर प्रधानमंत्री श्री मोदी की दृष्टि की सराहना की। श्री आबे ने आशा जाहिर की कि भारत अहमदाबाद-मुंबई रूट पर शिंकांसेन प्रणाली लागू करेगा। प्रधानमंत्री श्री आबे ने कहा कि जापान शिंकांसेन प्रणाली के लिए आर्थिक, तकनीकी और संचालनगत सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी शिंकांसेन प्रणाली की सराहना की है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अहमदाबाद-मुंबई रूट पर हाई स्पीड रेल सिस्टम की व्यावहारिकता का संयुक्त रूप से अध्ययन पूरा करने की उम्मीद जाहिर की।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्तमान में चल रही भारत-जापान आर्थिक साझेदारी की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का स्वागत किया और इसे तेजी से पूरा करने के लिए दृढ़ता जाहिर की। इन परियोजनाओं में से कुछ हैं . डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी), चेन्नई-बंगलुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी)। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन कॉरिडोर में नए स्मार्ट शहरों और औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए जापानी निवेशकों को आमंत्रित किया। भारत में शहरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विकास में जापान के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना में जापान से सहयोग की उम्मीद जाहिर की। प्रधानमंत्री श्री आबे ने कहा कि जापान इस परियोजना को आपसी हितों के आधार पर सहयोग करने के लिए तैयार है।

दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आयातित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता और ऊर्जा आपूर्ति में अचानक आने वाली रुकावटों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने आगे ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को भारत-जापान द्विपक्षीय बातचीत के जरिये मजबूत करने की अपनी इच्छा पर दृढ़ता जाहिर की। दोनों ने इस बात की भी इच्छा जाहिर की कि भारत और जापान वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस बाजार में उच्चस्तरीय रणनीतिक सहयोग की संभावना तलाशेंगे। इसमें एलएनजी की संयुक्त खरीद, तेल और गैस का धारा के प्रतिकूल विकास और लचीले एलएनजी बाजार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर प्रयास करना शामिल होगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पर्यावरण हित के लिहाज से हितकर और बेहद सक्षम, कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल करने और स्वच्छज कोयला तकनीक (सीसीटी) में सहयोग बढ़ाने का स्वागत किया।

दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक करार के तहत भारत से जापान को दुर्लभ खनिज क्लोराइड के उत्पादन और पूर्ति किये जाने का स्वागत किया। इस ठोस समझौते के तहत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसे जल्दी से जल्दी अंतिम रूप देने और इसके वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत करने की पुष्टि की है।

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) वार्ता में सक्रिय भागीदारी निभाने और इसे आधुनिक रूप से उच्च स्तर का बनाने व आपसी आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत पारस्परिक तौर पर लाभप्रद बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने आरसीईपी वार्ता में नतीजे पर पहुंचने के लिए आगामी सहयोग का फैसला किया।

विज्ञान, प्रेरणादायक नव-प्रवर्तन और विकसित प्रौद्योगिकी

दोनों प्रधानमंत्रियों ने शिक्षा, संस्कृति, खेल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल में हुई मंत्री स्तरीय सार्थक चर्चा पर संतोष जताया और उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने प्रतिभावान लोगों के लिए नये अवसर पैदा करने के वास्ते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नव-प्रवर्तन, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने संबंधों का पूरे सामर्थ्य के साथ उपयोग कर सकते हैं।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्टीम सेल अनुसंधान, भौतिक विज्ञान, ज्ञान-विज्ञान, अंक गणित का इस्तेमाल, कम्प्यूटर और सूचना विज्ञान, महासागर संबंधी तकनीक, महासागर निगरानी, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु परिवर्तन विज्ञान और जल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने भारत और जापान में संयुक्त प्रयोगशालाओं को शुरू करने के महत्व

पर बल दिया। उन्होंने दोनों देशों की अनुसंधान एजेंसियों और प्रयोगशालाओं के बीच बढ़ते सहयोग का स्वागत किया और दोनों देशों के युवा वैज्ञानिकों और छात्रों के बीच अनुसंधान संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने को प्राथमिकता दी।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को

स्वीकार करते हुए लोगों से आपसी संपर्क और पारस्परिक समझ को बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस दिशा में उन्होंने पर्यटन, युवा आदान-प्रदान, शिक्षा सहयोग और संस्कृति आदान-प्रदान में बढ़ते सहयोग का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री श्री आबे ने डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रशंसा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आईसीटी विस्तृत सहयोग फ्रेमवर्क के द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री श्री आबे ने भारत को (सपोर्ट फॉर टूमारो) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने नालंदा विश्वरविद्यालय के पुनरुद्धार से सामाजिक विज्ञान समेत बढ़ती शैक्षणिक एवं अनुसंधान साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंजने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (हैदराबाद) और जबलपुर में स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान के माध्यम से हम भविष्य की चुनौतियों से भी निपट लेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने निर्णय लिया कि भारत और जापान के बीच छात्रों का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास किये जायेंगे और इसके साथ भारत में जापानी भाषा, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में सहयोग शुरू करने का स्वागत किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री आबे ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने उन प्रयासों के बारे में अवगत कराया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे समाज बनाने का प्रयास किया है, जिसमें सभी महिलाएं उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं की शक्ति को मान्यता देने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि देश की विकास यात्रा तथा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है।

भविष्य की ठोस तैयारी

भारतीयों और जापानियों के मौजूदा समय में एक साथ आने के बीच दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों की सफलता के महत्व को स्वीकार किया और दोनों देशों के बीच इस साझेदारी के निर्माण में पूर्व के नेताओं के बहुमूल्य योगदान के लिए आभार जताया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऐसे रिश्ते बनाने का निर्णय लिया, जिसमें इस शताब्दी में दोनों देशों की तरक्की की राह और इस क्षेत्र तथा दुनिया के स्वरूप को तय करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जापान में अपने भव्य स्वागत और प्रधानमंत्री श्री आबे, जापान की सरकार एवं लोगों के भावपूर्ण सत्कार पर अपनी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री श्री आबे ने वर्ष 2015 में अगली वार्षिक शिखर बैठक के लिए भारत की यात्रा के प्रधानमंत्री श्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार किया।

तथ्य पत्रः भारत और जापान-साझा विकास के लिए भागीदार

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के साथ वार्षिक शिखर बैठक की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को सहयोग कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में आपसी सहयोग और ज्यादा बढ़ाने का निर्देश दिया।

ढांचागत क्षेत्र

1. जापानी पक्ष ने अगली पीढ़ी की ढांचागत सुविधाओं के मॉडल के तौर पर गुजरात में 10 मेगावाट का कैनल-टॉप ग्रिड कनेक्टिड सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए) द्वारा संभाव्यता अध्ययन शुरू करने की घोषणा की।
2. भारतीय पक्ष ने जापान से सार्वजनिक-निजी ढांचागत वित्त पोषण परियोजना के लिए इंडिया इन्फ्रा स्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल) को 50 अरब येन (तकरीबन 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का ऋण और

असम में गुवाहाटी सीवरेज परियोजना के लिए तकरीबन 15. 6 अरब येन (लगभग 156 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का कर्ज मिलने की सराहना की।

3. दोनों पक्षों ने यह माना कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी) परियोजना से भारत के छह राज्यों में नई पीढ़ी की स्मार्ट कम्युनिटी परियोजनाओं के सृजन के साथ औद्योगिक ढांचागत विकास में एक नया युग शुरू हो सकता है।

4. दोनों पक्षों ने माना कि डी.एम.आई.सी परियोजना नए विनिर्माण केंद्रों के अलावा ढांचागत संपर्कों जैसे विद्युत संयंत्रों, निश्चित जलापूर्ति, उच्च. क्षमता वाले शहरी परिवहन एवं ढुलाई की सुविधाओं के साथ-साथ युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम इत्यादि का भी रास्ता साफ करेगी।

5. दोनों पक्षों ने गुजरात के धोलेरा एवं महाराष्ट्र के शेंद्र-बिदक में औद्योगिक शहर और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा तथा मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट विक्रम उद्योगपुरी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की दिशा में हो रही प्रगति का स्वावगत किया।

6. दोनों पक्षों ने सर्वाधिक उपयुक्ति वित्तपोषण योजना को अपनाए जाने की संभावना के साथ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स (एम.आर.टी.एस) में जापानी तकनीकों का उपयोग किए जाने और जापानी निवेश बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई। दोनों पक्षों ने अपने संबंधित अधिकारियों को हरियाणा के गुड़गांव और बावल के बीच एम.आर.टी.एस के वास्तें येन में संभावित कर्ज के लिए जे.आई.सी.ए द्वारा संभाव्यता अध्ययन कराने का निर्देश दिया।

7. स्मार्ट कम्युनिटी परियोजनाओं जैसे लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक प्रोजेक्ट, नीमराना में मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट और दाहेज में सीवॉटर डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट में हुई प्रगति का स्वागत करते हुए दोनों पक्षों ने अपने अधिकारियों को इन स्मोर्ट कम्युननिटी परियोजनाओं पर अमल में तेजी लाने का निर्देश दिया। भारतीय पक्ष ने दाहेज स्थित सीवॉटर डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट से जुड़े लंबित मसलों को सुलझाने का आश्वासन दिया जिनमें शुल्क, जल की गुणवत्ता के पैमाने, जल बिक्री इत्यादि शामिल हैं। दोनों पक्षों ने उम्मीद जताई कि इन परियोजनाओं से भारत में उन्नत जापानी तकनीक का अनोखापन सामने आएगा।

8. चेन्नई-बंगलुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सी.बी.आई.सी), जिसमें दृष्टिपरक योजना को अंतिम रूप देना और तीन शहरों जैसे तमिलनाडु के पोन्नेबरी, आंध्र प्रदेश के कृष्णपतनम और कर्नाटक के टुमकुर को संभावित औद्योगिक केंद्र के रूप में डिजाइन करना भी शामिल है, में तेज प्रगति का स्वागत करते हुए दोनों पक्षों ने अपने अधिकारियों को मार्च 2015 के आखिर तक तीनों शहरों का मास्टर प्लान और विकास योजना बनाने के काम को अंतिम रूप देने में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम (टी.एन.आई.पी.पी) में उल्लेखित ढांचागत सुविधाओं के विकास को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया जिनमें सड़क विकास, बिजली और जलापूर्ति शामिल हैं। जापानी पक्ष ने इसका स्वागत किया।

9. भारत के कारोबारी माहौल में सुधार और ढांचागत विकास पर टी.एन.आई.पी.पी के सकारात्मक असर को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने यह विचार साझा किया कि इसी तरह का कार्यक्रम कर्नाटक राज्य में भी चलाया जा सकता है।

10. दोनों पक्षों ने सड़कों और सड़क परिवहन के क्षेत्र में भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और जापान के भूमि, ढांचागत, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के बीच एक सहयोग करार पर हुए हस्ताऔक्षर का स्वागत किया।

11. भारतीय पक्ष ने गुजरात के अलग सोसिया स्थित शिप-ब्रेकिंग यार्ड को उन्नत बनाने में जापान से मदद मांगी।

12. जापानी पक्ष ने समावेशन पर जोर के साथ लोकोन्मुपखी निवेश को बढ़ावा देने की जापान की नीति को रेखांकित किया जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को निवेश के आर्थिक लाभ, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और क्षमता निर्माण के प्रति बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता का लाभ मिल सके। जापानी पक्ष ने जोर देकर कहा कि ऐसे निवेश को बढ़ावा देने से टिकाऊ विकास हासिल होगा। भारतीय पक्ष ने इस नीति का स्वागत किया।

13. दोनों पक्षों ने एशियाई विकास बैंक से क्षेत्रों की ढांचागत और कनेक्टिविटी जरूरतों को पूरी करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने की अपील की।

निवेश

14. दोनों पक्षों ने बिजनेस लीडर फोरम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सराहना की और निप्पकन कैडनरेन द्वारा आयोजित एक उच्चस्तरीय आर्थिक मिशन की भारत यात्रा के प्रस्ताव का समर्थन किया।

15. दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इक्कीसवें अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेले (आई.ई.टी. एफ 2015) में जापान के साझेदार देश बनने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार होगा।

ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन

16. दोनों पक्षों ने अपने इरादों की पुष्टि की कि वे भारत-जापान

ऊर्जा बातचीत के जरिए ऊर्जा कुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला आधारित बिजली उत्पादन तकनीक क्षेत्र सहित ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

17. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जे.बी.आई.सी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर का दोनों पक्षों ने स्वागत किया।

18. दोनों पक्षों ने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और मरम्मत तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने में सहयोग जैसी स्वच्छ कोयला तकनीकों (सी.सी.टी) की प्रगति और उच्च कार्यकुशलता वाले एवं पर्यावरण अनुकूल कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का स्वागत किया।

19. दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश के मेजा में अत्यंत जरूरी कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जे.बी.आई.सी) के बीच हुए ऋण समझौते और बिहार में बरुआनी सुपर क्रिटिकल थर्मल ऊर्जा संयत्र के लिए संभावित ऋण परियोजना के लिए जे.आई.सी.ए द्वारा संभाव्यता अध्ययन की शुरुआत का स्वागत किया।

20. भारत-जापान रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी की दिशा में सार्थक कदम के तौर पर दुर्लभ धरा के उत्पादन के लिए इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आई.आर.ई.एल) और टोयोटा सूशो कोर्पोरेशन (टी.टी.सी) के बीच वाणिज्यिक अनुबंध आधार पर हुए जरूरी समझौते का दोनों पक्षों ने स्वागत किया और वाणिज्यिक उत्पादन के साथ-साथ वाणिज्यिक अनुबंधों की शुरुआत को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की अपनी मजबूत इच्छाशक्ति को दोनों पक्षों ने दोहराया।

21. दोनों पक्षों ने भारत में इस्पात, सीमेंट और यांत्रिक उपकरणों सहित ऊर्जा कुशलता में सुधार के लिए सहयोगी प्रयत्नों की प्रगति का स्वागत किया। दूरसंचार टॉवरों में ऊर्जा प्रबंधन व्यवस्था के लिए आदर्श परियोजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एन.ई.डी.ओ) द्वारा अगस्त 2014 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) की सराहना की। भारत में जनवरी 2014 में नवीकरणीय ऊर्जा पर हुई पहली भारत-जापान पब्लिक-प्राइवेट गोलमेज वार्ता के बाद नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यावसायिक सहयोग पर चर्चा की प्रगति की भी दोनों पक्षों ने सराहना की।

22. सितंबर 2014 में भारत में नीडो (एन.ई.डी.ओ) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और व्यवसाय मिलान गतिविधियों का दोनों पक्षों ने स्वागत किया।

23. दोनों पक्षों ने 2015 में लौह अयस्क व्यापार प्रबंधन के नवीकरण में प्रगति का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने भविष्य में भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग में निवेश एवं तकनीक के संबंध में सहयोग बढ़ाने के महत्व की बात स्वीकार की।

कृषि एवं खाद्यान्न

24. भारत में खाद्यान्न संबंधी अवसंरचना स्थापित करने और कृषि विकास के महत्व को स्वीकारते हुए, दोनों पक्षों ने जापान द्वारा अग्रणी सिंचाई व्यवस्था और खेती मशीन की शुरुआत के द्वारा निजी-सार्वजनिक भागीदारी के जरिए खाद्य मूल्य चेन स्थापित करने के जापान के कदम का स्वागत किया। जापान के इस कदम के जरिए भारत सरकार द्वारा लागू खाद्य औद्योगिक पार्कों और शीत चेन विकास परियोजनाओं को भी समर्थन मिलेगा।

रेलवे

25. दोनों पक्षों ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल की अंतरिम रिपोर्ट जारी किए जाने का स्वागत किया और उम्मीद जताई की संयुक्त संभाव्यता अध्ययन जुलाई 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

26. दोनों पक्षों ने वर्तमान रूटों पर सेमी-हाई स्पीड रेलवे व्यवस्था के तहत पैसेंजर रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखने को स्वीकृति दी।

27. भारत में विभिन्न मेट्रो और अन्य शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए जापानी ओ.डी.ए की महत्वपूर्ण भूमिका की भारत ने जमकर सराहना की। दोनों पक्षों ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना में सहयोग का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने भारत में मेट्रो एवं अन्य शहरी अवसंरचना परियोजनाओं सहित विभिन्न उपयुक्त अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में भारत-जापान सहयोग बढ़ाने के लिए संभावनाएं तलाशने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने भावी मेट्रो परियोजनाओं में परस्पर लाभकारी तरीके से ओ.डी.ए सहायता जारी रखने के महत्व को स्वीकार किया।

नागरिक उड्डयन

28. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के महत्व को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया, जोकि परस्पर आदान-प्रदान को बढ़ाने में योगदान देगा। दोनों पक्षों ने नव धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा विकास परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण को गति देने सहित विभिन्न मामलों में सहयोग मजबूत करने का निर्णय लिया।

कौशल विकास

29. बेहतर कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की जारी योजनाओं

के प्रयत्नों को स्वीकारते हुए दोनों पक्षों ने भारत में विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारों में स्थानीय युवाओं के क्षमता विकास और कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास को एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में स्वीकार किया और डी.एम.आई.सी परियोजना में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए द ओवरसीज ह्यूमेन रिसोर्सिज एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन (एच.आई.डी.ए) के सहयोग की सराहना की।

30. दोनों पक्षों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए जापान के बहुमूल्य योगदान के रूप में चौंपियन सोसायटी मैन्युफैक्चरिंग (सी.एस.एम) की उपलब्धियों की सराहना की। भारत ने विलेज बुद्धा नामक जापान की नई उप-परियोजना की शुरुआत का स्वागत किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वंयसहायता समूहों में नेतृत्व विकास करना है साथ ही इन समूहों में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी बताना है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

31. भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के आंतरिक मामले एवं संचार मंत्रालय के बीच भारत-जापान आई.सी.टी समग्र सहयोग संरचना के तहत संयुक्त कामगार समूहों की गतिविधियों के जरिए आई.सी.टी सहयोग की प्रगति का दोनों पक्षों ने स्वागत किया।

32. फरवरी 2014 में प्रथम संयुक्त कामगार समूह के समझौते पर आधारित हरित आई.सी.टी और साइबर सुरक्षा सहयोग जैसी ठोस संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया और आई.सी.टी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दोबारा पुष्टि की।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण

33. भारत ने मार्च 2015 में सेंदई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र विश्व कॉन्फ्रेंस की जापान द्वारा मेजबानी किए जाने का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने एक्शन 2005-2015 के लिए ह्योगो रूपरेखा के कामयाब ढांचे को अपनाने के क्रम में कॉन्फ्रेंस के शुरू से लेकर अंत तक सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग

34. दोनों पक्षों ने पूर्वोत्तर भारत और पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क पर जे.आई.सी.ए के अध्ययन का स्वागत किया और क्षेत्र में परिवहन आधारभूत परियोजनाओं में जापानी ओ. डी.ए को शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत और पड़ोसी देशों के बीच आधारभूत विकास सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय आयात-निर्यात बैंक और जे.बी.आई.सी के बीच सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया।

35. दोनों पक्षों ने पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने का फैसला किया। जापानी पक्ष ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क संपर्क परियोजनाओं सहित संभावित सहयोग की पहचान के लिए जे.आई.सी.ए से एक सर्वे कराने की घोषणा की। भारतीय पक्ष ने वन्य संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में कई परियोजनाओं समेत पूर्वोत्तर भारत में जापान की मदद की सराहना की। इसके साथ ही भारतीय पक्ष ने मणिपुर के इम्फाल में जलापूर्ति सुधार के लिए येन मुद्रा में संभावित ऋण और जे.आई.सी.ए के संभाव्यता अध्ययनों की भी प्रशंसा की।

अफ्रीका में सहयोग

36. दोनों पक्षों ने अफ्रीका में अपने सहयोग को मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। दोनों पक्षों ने अफ्रीका में भारतीय और जापानी निवेशकों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने अफ्रीका पर भारत-जापान वार्ता के अगले दौर के महत्व की पुष्टि की।

समुद्री मामले

37. दोनों पक्षों ने ज्वायइंट वर्किंग ग्रुप को यूएस-2 एम्फीबिएन विमान सहयोग के द्वारा भारतीय विमान उद्योग के विकास के लिए रोडमेप की तैयारियों और विचार-विमर्श की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए।

38. भारतीय पक्ष ने रक्षा उपकरण प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की अपनी इच्छा- जाहिर की और इस बारे में अपने हितों से जापानी पक्ष को अवगत कराया। दोनों पक्षों ने भविष्य मे सहयोग के और क्षेत्रों की पहचान करने पर चर्चा करने का फैसला किया।

39. दोनों पक्षों ने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक और जापान तटरक्षक बल के कमांडेंट के बीच वार्ता और जनवरी, 2014 को कोच्चि तट पर भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने समुद्री मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की अपनी इच्छा जताई और टोक्यो में अगली द्विपक्षीय वार्ता और अक्टूबर 2014 में भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों के बीच हानिदा तट पर संयुक्त अभ्यास करने का फैसला लिया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

40. दोनों पक्षों ने जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस (जे.एस.पी.एस) के फेलोशिप प्रोग्राम के तहत जापान में

अनुसंधान का अनुभव लेने वाले भारतीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा आयोजित विकाशील अनुसंधानकर्ताओं के नेटवर्क का स्वाागत किया।

41. भारतीय पक्ष ने युवा भारतीय शोधकर्ताओं और छात्रों को जे.एस.पी.एस छात्रवृत्ति कार्यक्रम और विज्ञान से संबंधित जापान-एशिया युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से

अपने देश में आमंत्रित करने की जापानी पक्ष की मंशा का स्वागत किया है।

42. दोनों पक्षों ने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और जापान की समुद्र-पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी (जे.ए.एम.एस.टी.ई.सी) के बीच महासागर और पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये सहयोग की शुरूआत करने के संबंध में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया है। इस सहयोग में समुद्र की निगरानी, जलवायु की असमानताओं तथा हिंद महासागर और गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का भूभौतिकीय अध्ययन शामिल है।

43. त्सुककुबा में हाई-एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (के.ई.के) में सफल इंडियन बीम लाइन के संचालन की सराहना, सहयोग की प्रमुख गतिविधि के रूप में करते हुए दोनों पक्षों ने संरचनात्मरक सामग्री विज्ञान (स्ट्रक्चरल मटिरियल साइंस) में इस सहयोग को एडवांस्ड मैटिरियल्से के अध्ययन के दूसरे चरण तक ले जाने के फैसले की घोषणा की है।

44. दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एशिया-प्रशांत अंतरिक्ष एजेंसी फोरम (ए.पी.आर.एस.ए.एफ) जैसे दृष्टिकोण के माध्यम से सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है और आशा व्यक्त की है कि जापान एयरोस्पेस एक्सयप्लोरेशन एजेंसी (जे.ए.एक्सप.ए.) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इस सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

45. दोनों पक्षों ने भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया है।

46. दोनों पक्षों ने चिकित्सा उपकरणों के विकास को बढ़ावा दिये जाने की आशा की व्यक्त की है, जो संयुक्तो अनुसंधान एवं विकास की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाशन (एम्स) और ओसाका विश्वविद्यालय की नये पहल के जरिये भारतीय जरूरत पूरी करेंगे।

47. दोनों पक्षों ने जापानी कम्पनी और भारतीय अस्पताल के बीच सहकारी प्रारूप में एडवांस कैंसर निदान और उपचार केंद्र की स्थीपना के संदर्भ में कारोबार के प्रोत्साहन पर हाल में हुई प्रगनति पर संतोष व्यक्त किया है।

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान सहयोग

48. दोनों पक्षों ने जापान सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस (जे.एस.पी.एस) और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर) तथा जेएसपीएस और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर) के बीच दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षरों का स्वागत किया है।

जनता के बीच आदान-प्रदान

49. दोनों पक्षों ने जे.ई.एन.ई.एस.वाई.एस 2.0 कार्यक्रम के तहत दोनों देशों के करीब 1300 युवाओं के आदान-प्रदान के संबंध में जारी योजना पर संतोष व्यक्त. किया है।

50. भारतीय पक्ष ने भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ जापानी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सहयोग को सहायता देने संबंधी जापान की पहल और समन्वयकों को भारत भेजने सहित कार्यों का स्वागत किया है।

51. दोनों पक्षों ने पर्यटन में सहयोग के महत्व पर बल दिया है और पर्यटन प्रदर्शनियों के जरिये अपने नागरिकों को एक-दूसरे की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के वर्तमान प्रयासों का स्वागत किया है। ■

असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग करार एक ऐतिहासिक कदम : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री टोनी एबोट की भारत यात्रा पर उनका स्वागत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मेरी सरकार के वे पहली राजकीय यात्रा के माननीय अतिथि हैं। यह हमारा सौभाग्य है क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया को बहुत महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है और इन संबंधों को और गहरा बनाना चाहता है।

हम दोनों शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों में विविधता है। हिन्द महासागर से हम दोनों जुड़े हुए हैं। भारत के विकास में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, क्योंकि भारत संसाधनों की कमी महसूस करने वाला देश है और भारत की आवश्यकताएं बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया पूरी कर सकता है। ढांचागत और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में भी विशाल संभावनाएं हैं। आने वाले समय में भारत अत्यंत कुशल मानव संसाधन का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है।

शिक्षा, विज्ञान और कौशल विकास के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया में चार लाख से भी अधिक भारतीय समुदाय के निवासी हैं जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और दोनों देश के संबंधों को गहरा कर रहे हैं।

हिन्द महासागर क्षेत्र में और एशिया-प्रशांत में शांति और विकास को आगे बढ़ाना है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को आपसी सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी और अन्य देशों को इस काम में जोड़ने में नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी।

प्रधानमंत्री एबोट और मैंने इन सभी क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा करने के उपायों पर सार्थक बातचीत की है।

सबसे पहले 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारत से चुरायी हुई दो प्राचीन मूर्तियों को स्वयं साथ लाकर भारत को वापस सौंपा है। जैसे ही उनकी सरकार को इन मूर्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत शीघ्रता से यह निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री एबोट ने केवल हमारी संपत्ति का ही आदर नहीं किया है, बल्कि हमारी संस्कृति की ओर सम्मान की भावना प्रकट की है।

आज संपन्न हुआ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग करार एक ऐतिहासिक कदम है। यह हमारे आपसी विश्वास और भरोसे का बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे सहयोग में एक नए अध्याय का शुभारंभ करेगा। परमाणु ऊर्जा भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन पदार्थों पर निर्भरता कम करेगी।

हम अपने राजनीतिक संवाद और रक्षा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करेंगे। इस क्षेत्र में हम ऑस्ट्रेलिया को एक महत्वपूर्ण पार्टनर मानते हैं। जनप्रतिनिधियों के बीच आदान-प्रदान भी बढ़ायेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मीडिया को दिए गए वक्तव्य का मूल पाठ

आज संपन्न हुआ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग करार एक ऐतिहासिक कदम है। यह हमारे आपसी विश्वास और भरोसे का बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे सहयोग में एक नए अध्याय का शुभारंभ करेगा। परमाणु ऊर्जा भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन पदार्थों पर निर्भरता कम करेगी। हम अपने राजनीतिक संवाद और रक्षा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करेंगे। इस क्षेत्र में हम ऑस्ट्रेलिया को एक महत्वपूर्ण पार्टनर मानते हैं। जनप्रतिनिधियों के बीच आदान-प्रदान भी बढ़ायेंगे।

1986 के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नहीं गया है। मैं नवंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय दौरा करूंगा। हम दोनों का प्रयास रहेगा कि जब भी हो सके आपसी बातचीत का सिलसिला जारी रहे।

मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर भी हम अपने संवाद को बढ़ायेंगे। राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में। साथ ही साथ हम हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे मंचों में अपने संवाद और सहयोग को गहरा बनायेंगे।

अगले साल हमारी पहली द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास होगी। आने वाले समय में हम इसे और आगे बढ़ायेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न तरह से, जैसे मानवीय सहायता है, हम बहुत योगदान दे सकते हैं। हम प्रथम विश्वयुद्ध, जिसमें हमारे सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, के 100वें साल के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे।

आतंकवाद, साइबर खतरा और अन्य समस्याओं के खिलाफ भी हमारी साझेदारी बढ़ेगी। हमारे बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। भारत की कंपनियां, जो ऑस्ट्रेलिया में निवेश करना चाहती हैं, उनको प्रधानमंत्री एबोट की सरकार ने सहायता दी है और उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया है कि निवेश निर्णयों को तेजी से संपन्न करेंगे। हम भारत में ढांचागत, उच्च प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा निवेश का स्वागत करेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आ गई थी। हमने तय किया है कि हम जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईसीए) को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है कि आज हम ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान फंड के लिए नए वित्त पोषण की घोषणा कर रहे हैं। इस कोष का उपयोग हम ऊर्जा, खाद्य, जल, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए करते हैं।

प्रधानमंत्री एबोट ने भारत में युवा ऑस्ट्रेलियाई छात्रों की पढ़ाई के लिए एक नए कोलंबो प्लान की घोषणा की है। युवाओं के आदान-प्रदान से आपसी समझ और मित्रता बढ़ेगी।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को ऑस्ट्रेलिया के समर्थन की हम सराहना करते हैं। मैं ब्रिस्बेन में जी-20 शिखर सम्मेलन की राह देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री एबोट के नेतृत्व में जी-20 वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। 2015 के आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस शिखर सम्मेलन से बहुत संतुष्ट हूं। नवंबर के शिखर सम्मेलन में उसे हम और आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारत की 'पूरब की ओर देखो नीति' का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा और हर क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार होगा।

प्रधानमंत्री एबोट ने कौशल विकास जो मेरे लिए एक प्राथमिकता का विषय है, में हमारे सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने का आश्वासन दिया है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर विश्वविद्यालय के स्तर पर, हमारे सहयोग बढ़ें ताकि भारत के युवाओं के लिए विश्व स्तारीय शिक्षा के अवसर बढ़ें।

क्रिकेट और हॉकी से तो हम दो देश जुड़े ही हैं। पर मैंने आग्रह किया है कि भारत में खेल-कूद विश्वेविद्यालय बनाने में ऑस्ट्रेलिया का सहयोग मिले।

विद्यार्थियों और दोनों देशों के बीच पर्यटकों की बढ़ती संख्या हमारे जन संपर्क का विस्तार कर रही है।

बहुपक्षीय मंचों में हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को ऑस्ट्रेलिया के समर्थन की हम सराहना करते हैं। मैं ब्रिस्बेन में जी-20 शिखर सम्मेलन की राह देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री एबोट के नेतृत्व में जी-20 वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। 2015 के आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं।

मैं इस शिखर सम्मेलन से बहुत संतुष्ट हूं। मुझे विश्वास है कि आज की मुलाकात के बाद इन संबंधों को नई गति मिलेगी। आज हमने कई विषयों पर बात की है। नवंबर के शिखर सम्मेलन में उसे हम और आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारत की 'पूरब की ओर देखो नीति' का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा और हर क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार होगा। ■

प्रधान मंत्री जन धन योजना का शुभारंभ

गरीबी से आजादी के लिए वित्तीय छुआछूत खत्म करें : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अनुमानित 1.5 करोड़ बैंक खाते खुलने के साथ ही भारत में वित्तीय छुआछूत की समाप्ति का शुभारंभ होने का ऐलान किया। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में बैंक खाते खुलना आर्थिक इतिहास में एक अप्रत्याशित रिकॉर्ड है।

गत 28 अगस्त को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से देश भर में प्रसारित एक समारोह में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का औपचारिक रूप से शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को ''विष-चक्र से गरीबों की आजादी का पर्व'' करार दिया।

एक ही दिन में कई रिकॉर्ड टूटने पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक खाते खोलने के अभियान को आज मिली राष्ट्र व्यापी सफलता से न केवल वित्तीय सेवा विभाग और बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों का, बल्कि केंद्र सरकार के अधिकारियों का भी इस बात पर भरोसा बढ़ेगा कि वे उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं, जिन्होंने वे खुद के लिए तय करते हैं। उन्होंने कहा, 'आज से पहले बीमा कंपनियों ने कभी भी एक ही दिन में 1.5 करोड़ दुर्घटना बीमा पॉलिसियां जारी नहीं की होंगी। आर्थिक इतिहास में आज से पहले कभी भी एक ही दिन में 1.5 करोड़ बैंक खाते नहीं खुले होंगे। आज से पहले कभी भी भारत सरकार ने एक ही दिन में 77,000 से भी ज्यादा स्थानों पर एक जैसा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है, जिसमें इतने सारे

एक ही दिन में कई रिकॉर्ड टूटने पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक खाते खोलने के अभियान को आज मिली राष्ट्र व्यापी सफलता से न केवल वित्तीय सेवा विभाग और बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों का, बल्कि केंद्र सरकार के अधिकारियों का भी इस बात पर भरोसा बढ़ेगा कि वे उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं, जिन्होंने वे खुद के लिए तय करते हैं। उन्होंने कहा, 'आज से पहले बीमा कंपनियों ने कभी भी एक ही दिन में 1.5 करोड़ दुर्घटना बीमा पॉलिसियां जारी नहीं की होंगी। आर्थिक इतिहास में आज से पहले कभी भी एक ही दिन में 1.5 करोड़ बैंक खाते नहीं खुले होंगे। आज से पहले कभी भी भारत सरकार ने एक ही दिन में 77,000 से भी ज्यादा स्थानों पर एक जैसा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और सरकारी एवं बैंक अधिकारियों ने शिरकत की।' उन्होंने कहा कि यह सफलता नई ऊंचाइयां छूने की दिशा में एक प्रेरणा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैसे तो 'पीएमजेडीवाई' का आरंभिक लक्ष्य एक साल में 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलना है, लेकिन हमने संबंधित अधिकारियों से अगले गणतंत्र दिवस से पहले ही इस अहम कार्य को पूरा करने के लिए कहा है।

'पीएमजेडीवाई' के तहत मिलने वाले फायदों को विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महज एक बैंक खाता नहीं है क्यों कि इसमें अन्य लाभ भी हैं, जिनमें एक रुपेए डेबिट कार्ड, एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और अतिरिक्त 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी शामिल हैं। ये लाभ उन सभी लोगों को मिलेंगे जो 26 जनवरी, 2015 से पहले बैंक खाता खोलेंगे। उन्होंने कहा कि इन खातों में होने वाले लेन-देन पर नजर रखी जाएगी तथा ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 7.25 लाख बैंक कर्मचारियों को भेजकर उनसे 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलने के लक्ष्य को पाने और वित्तीय छुआछूत से आजादी दिलाने में मदद करने को कहा है।

प्रधानमंत्री ने उन पांच लाभार्थी दम्पतियों का जिक्र किया जिन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान खाता खोलने वाली किट हासिल की थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की वेशभूषा किसी समारोह में शामिल होने जैसी थी। उन्होंने कहा, 'वे जानती थीं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते खोलने से बड़ा कोई और समारोह नहीं हो सकता।'

प्रधानमंत्री ने कहा, ''जब वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब लोगों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना लक्ष्य था। हालांकि, वह उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आजादी के 68 साल गुजर गए हैं, लेकिन देश की 68 फीसदी आबादी को भी अब तक बैंकिंग सुविधा नसीब नहीं हो पाई है।'' उन्होंने कहा, ''अमीरों को तो आसानी से सस्ता लोन मिल जाता है, लेकिन गरीबों को विवश होकर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अमीरों के मुकाबले पांच गुना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। क्या यह बैंक उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है कि वह गरीबों को बैंकिंग सुविधा सुलभ कराए।''

अमीरों को तो आसानी से सस्ता लोन मिल जाता है, लेकिन गरीबों को विवश होकर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अमीरों के मुकाबले पांच गुना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। क्या यह बैंक उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है कि वह गरीबों को बैंकिंग सुविधा सुलभ कराए।

प्रधानमंत्री ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जिसमें बचत करने वाली एक ऐसी मां का जिक्र किया गया है, जो इस राशि को अपने घर में कहीं छिपाने पर विवश हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिन बैंक अधिकारियों ने इस तरह की मां के लिए खाता खोला है, वे आज खुद को भाग्यवान महसूस कर रहे होंगे।

उन्होंने कहा कि गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए एक बड़े कदम की जरूरत थी, जिसे आज सफलतापूर्वक उठाया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों की पहुंच मोबाइल फोन तक होने और डेबिट कार्ड तक उनकी पहुंच होने में समानताएं हैं। दोनों ही कदमों से गरीबों का विश्वास और गर्व बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर संस्कृत भाषा की एक प्राचीन उक्ति का जिक्र किया: सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्यं मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। इसके मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों में लोगों को शामिल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस सरकार ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों में बचत करने की आदत है और वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिन्तित रहते हैं।

प्रधानमंत्री ने इस योजना के लिए 'नाम और प्रतीक चिह्न प्रतियोगिता' के विजेताओं को पुरस्कार दिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाले अधिकतर गैर-हिन्दी भाषी राज्यों से हैं लेकिन उन्होंने नाम और लोगो हिन्दी में बनाने के लिए पुरस्कार जीते हैं। यह राष्ट्रीय एकीकरण का एक उदाहरण है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमजेडीवाई को मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा और बैंक से अब तक नहीं जुड़े 7.5 करोड़ परिवारों को बैंकिंग सुविधा सुलभ कराने के प्रथम लक्ष्य को 26 जनवरी 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

वित्त राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएमजेडीवाई में घर की महिला को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना सकारात्मक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगी। ■

शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री ने छात्रों से बातचीत की

शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ताकत बननी चाहिए : नरेंद्र मोदी

शिक्षक दिवस पर पूरे देश के छात्रों के साथ अनूठे संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि बदली हुई दुनिया में डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस की प्रासंगिकता की फिर से व्याख्या करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक के महत्व को उभारने की बहुत जरूरत है और समाज में शिक्षकों के सम्मान को फिर से स्थापित करना होगा, तभी शिक्षक नई पीढ़ी को सांचे में ढाल सकेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वभर में अच्छे शिक्षकों की बहुत मांग है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या भारत अच्छे शिक्षकों को विश्व भर में भेजने का सपना नहीं देख सकता?

प्रधानमंत्री ने लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को रेखांकित करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण का जिक्र किया जिसमें उन्होंने एक साल के भीतर सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ देने यानि ड्रॉप-आउट को कम करने के लिए सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा की एक छात्रा के उस प्रश्न पर खुशी जाहिर की जिसमें दंतेवाड़ा में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी और लड़कियों की शिक्षा की पहल से जुड़े प्रयासों को लेकर प्रश्न किया गया था। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे उस इलाके जहां की धरती माओवाद के कारण लहूलुहान हो चुकी है वहां की एक लड़की का यह प्रश्न देश को जागृत कर सकता है।

छात्रों से बातचीत और उनके ढेर सारे सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाल की जापान यात्रा का हवाला दिया और बताया कि कैसे वे वहां की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि जापान में शिक्षक और छात्र मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं-यह उनके चरित्र निर्माण का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या हम इसे अपने देश के चरित्र निर्माण का हिस्सा नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री ने जापान की शिक्षा व्यवस्था में शामिल अनुशासन, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक रूझान पर भी जोर दिया।

गुजरात में अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम ''वांचे गुजरात'' (गुजरात पढ़ो) की तरह देश भर में इस तरह का कार्यक्रम शुरू किए जाने के सवाल पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का हवाला दिया और कहा कि उन्हें आशा है कि सभी लोग जुड़ पाने और ज्ञान तक पहुंच पाने की अपनी जरूरत पूरी कर सकेंगे। एक अन्य प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने देश के प्रतिष्ठित नागरिकों को सलाह दी कि वे अपने पास के स्कूल में सप्ताह में कम से कम एक पीरियड पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने छोटे-छोटे कामों के जरिए जैसे कि सफाई रखकर और बिजली-पानी की बचत कर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास

झारखंड

प्रदेश में भाजपा की सरकार निश्चित : अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि इस सभा में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं का समागम हमारे सामने उपस्थित है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में दो-तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनना निश्चित है। आज किसी भी पार्टी में इतना माद्दा नहीं है कि इतनी बड़ी जनसभा कर ले और इतने कार्यकर्ताओं को जुटा ले।

चुनाव के बाद पहली बार मैं भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती पर आया हूं। सबसे पहले झारखंड की जनता और भाजपा के लाखों-लाख कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने 14 में से 12 भाजपा उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में विजयी बनाया और देश में एक मजबूत सरकार की नींव डाली।

देश में बहुत जरूरत थी इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, राष्ट्रभक्तों की सरकार बने। और झारखंड की जनता ने इस काम को बखूबी निभाया। बहुत अर्से बाद देश को एक बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है जो जनता के दुखों को सुनता है और उस पर मनन करता है।

15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया था। लाल किले के प्राचीर से पहले भी कई प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते आए हैं। लेकिन इस बार जब नरेंद्र भाई देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में सामने बिना बुलेट प्रुफ शीशे का भाषण दिया तो सारे देश के लोगों को लगा कि देश को अब एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वह जनता को सीधे संबोधित कर सकता है।

100 दिनों के अंदर हर क्षेत्र में ठोस शुरूआत हुई है फिर चाहे वह आर्थिक मोर्चा हो, विदेश नीति का मामला हो अथवा देश की सुरक्षा का मामला हो।

हमने सरकार गठन के दौरान सार्क देशों के सभी प्रमुखों को बुलाया। जब पड़ोसी देशों के मुखिया मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आए तो उन्हें भी महसूस हुआ कि भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है।

शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री आए। आप जानते हैं कि भारत व पाक के मध्य कई प्रश्नचिन्ह खड़े हैं। हम इसका समाधान चाहते हैं। हमने सचिव स्तर की वार्ता रखी। लेकिन वार्ता से पहले पाक की सरकार ने जैसे ही कश्मीर अलगाववादियों से बात की तो प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया कि अलगाववादी और हमसे, दोनों से साथ-साथ बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि या तो अलगाववादियों से बात करो या हमसे।

ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भी जिस प्रकार भारत को तवज्जो दी गई उससे स्पष्ट हुआ कि देश को एक मजबूत सरकार मिली है। ब्रिक्स बैंक का पहला मुखिया भारत से ही होगा, यह पक्ष सरकार ने मजबूती से रखा जिसमें कामयाबी भी मिली। देश की जीडीपी बढ़ी है, विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। बहुत दिनों बाद पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई है। महंगाई नियंत्रण के भी कई उपाय किए जा रहे हैं। महंगाई नियंत्रित तो हुई है लेकिन इसमें और भी कमी आएगी।

केंद्र की पिछली सरकार ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन को स्वदेश वापस लाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि यदि नाम उजागर हुई तो उन्हीं के रेले लग जाएंगे। लेकिन नई सरकार बनते ही काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। और विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध

हैं। केंद्र सरकार जन-भावना और जन-समस्याओं को जानती है इसीलिए जो योजना बन रही है, जनता के कल्याण के लिए बन रही है।

झारखंड में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूं कि आपके पिता जी अलग झारखंड निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे लेकिन आज आप उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं जो कभी कहा करते थे कि झारखंड का निर्माण मेरे लाश पर होगा।

मैं कार्यकर्त्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि वे अपना उत्साह बरकरार रखें। कौन जितेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसकी चिंता मत करें। चुनाव में विजय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बूथ जितने का संकल्प लें। मैं एक बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम झारखंड में आगामी विधानसभा का चुनाव श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं।

केरल

भाजपा केरल सहित सभी दक्षिणी राज्यों में मजबूत बनेगी

केरल में दृढ़ता से अपने कदम जमाने में भाजपा की सहायता के उद्देश्य से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 सितंबर में तिरूवनंतपुरम में कांग्रेस की यूडीएफ और सीपीएम-नीत एलडीएफ की साम्प्रदायिक तुष्टिकरण की आलोचना और इन पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति पर चल रही हैं और राज्य विकास

की उपेक्षा कर रही हैं।

जमीनी स्तर से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं के एक विशेष कंवेंशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने राज्य की अपनी पहली यात्रा में कहा कि यह स्पष्ट है कि ये दोनों गठनबंधन केरल-स्थित पीडीपी नेता अब्दुल नासिर मदानी को छोड़ने पर तैयार है जबकि उस पर बंगलौर बम-विस्फोट मामले में मुकदमा चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का प्रमुख नारा है। 'कांग्रेस-मुक्त भारत', अत: यदि यह लक्ष्य पूरी तरह सफल हो जाए तो कांग्रेस को केरल में हराया जा सकता है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अगले वर्ष के प्रारंभ में सिविक चुनावों तथा 2016 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस लें क्योंकि इस स्थान पर हम निरंतर चुनावी सफलता पाने में असफल रहे हैं।

श्री शाह ने यह बात भी साफ कर दी कि उनका उद्देश्य केरल सहित सभी दक्षिणी राज्यों एवं ओड़िशा में भी भाजपा को मजबूत बनाना है। इन राज्यों में असम और पश्चिम बंगाल को भी जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस और वामपंथियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब एनडीएफ सत्ता में थी तब राज्य विधान सभा ने मदानी को रिहा करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इससे भी आगे बढ़ कर कांग्रेस मुख्यमंत्री (ओमेन चाण्डी), खुद पीडीपी नेता से मिलने के लिए बंगलौर गए थे। वास्तव में ये दोनों मोर्चे साम्प्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।

श्री शाह ने यह भी कहा कि यह हैरत की बात है कि कांग्रेस आते ही सेक्युलर होने की बात करती हो परन्तु वह इण्डियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के साथ केरल में पार्टनरशिप बनाए हुए हैं। उनका आरोप था कि विकास की दिशा में राज्य को आगे न बढ़ा पाने पर ये गठबंधन, जो बारी-बारी से सत्ता में आते रहे, वे भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में एक-एक करके आगे आते रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर

दशकों के पुराने खानदानी शासन को समाप्त करें

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह अपने पार्टी राष्ट्रीय महासचिवों श्री जेपी नड्ढा और श्री राम माधव, प्रभारी जम्मू और कश्मीर श्री अविनाश राय खन्ना तथा सह-प्रभारी श्री आरपी सिंह के साथ 24 जुलाई को दो दिन के दौरे पर स्थानीय पार्टी नेताओं से बातचीत करने पहुंचे, जिसमें आने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शामिल थी। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की वर्तमान स्थिति और राज्य की

अन्य हालात भी देखे।

भाजपा ने आने वाले चुनावों में 44 प्लस का मिशन लेने की घोषणा की है और वरिष्ठ नेतागण सहित केन्द्र और भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने लगभग एक महीने तक राज्य में चर्चा करते हुए लोगों से मिले तथा जमीनी आधार तैयार किया जिससे कथित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और भाजपा सरकार 66 वर्षों में पहली बार बना सके।

भाजपा नेतागणों ने इस सभी यात्राओं में एनसी-कांग्रेस गठबंधन सरकार को उनकी विफलता के लिए भर्त्सना की तथा यह सरकार किसी मोर्चे पर सफल न होकर नितांत भ्रष्टाचार में फंसी रही और घाटी में साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों के कारण न तो कोई विश्वास रह गया है और न ही की कोई गवर्नेंस दिखाई पड़ती है। इस बात को रेखांकित किया कि आजतक एनसी-कांग्रेस मुक्त जम्मू और कश्मीर की है।

श्री अमित शाह ने अपनी यात्रा के दौरान आग्रह किया कि राज्य के लोगों को दशकों से चली आ रही खानदानी शासन को समाप्त कर देना चाहिए तथा भाजपा को जनादेश देकर राज्य को अन्य राज्यों के बराबर लाया जा सके तथा लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन का पुनरूद्धार हो सके। उन्होंने यह वक्तव्य 25 अगस्त को कठुआ की एक विशाल जन सभा के सम्बोधन में कहा।

9 अगस्त को भी, जब उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी पार्टी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से पद ग्रहण किया तो श्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से एक मन लगा कर, एकजुट होकर पूरे समर्पण भाव से काम करने की अपील की ताकि अब्दुल्ला का खानदानी शासन समाप्त हो जाए (जिसमें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तथा मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती शामिल है क्योंकि इन सभी ने राज्य के समाज को नुकसान पहुंचाया है। यहां कि अर्थव्यवस्था और राजनीति को लोगों की कीमत पर खराब किया है, जिससे राज्य और देश की गड्ढे में चला जाता है।) ■

महाराष्ट्र

शाह ने कांग्रेस-मुक्त महाराष्ट्र का आह्वान किया

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस-मुक्त महाराष्ट्र बनाने का आह्वान किया। विगत 15 दिनों में हमने कांग्रेस के कुशासन के कारण अनेकानेक घोटाले देखे। अब हमें कांग्रेस-मुक्त महाराष्ट्र बनाना है और यह आप ही लोग है, कार्यकर्ता है, जिन्होंने कांग्रेस को हटाया है। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस द्वारा किए सभी घोटालों से आक्रोशित है। जब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार रहेगी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'कांग्रेस-मुक्त भारत' का नारा पूरा नहीं हो पाएगा।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझे आशा है कि भाजपा महाराष्ट्र में फिर से सभी चीजों को ठीक करने के लिए सत्ता में आएगी।

श्री शाह ने कहा कि कोई समय था जब महाराष्ट्र की दक्षता पूरे देशभर में गुणगान होता था, जहां कोई भी व्यक्ति किसी एक भी राजनीतिज्ञ पर उंगली नहीं उठा पाता था और जिसने पूरे देश को सहकारी आंदोलन की नई दिशा दिखाई, ऐसे स्थान पर भाजपा को सत्तारूढ़ होना चाहिए। महाराष्ट्र में आने वाले चुनावों के लिए वह इस यात्रा मे रणनीति तैयार करेंगे।

श्री शाह पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद मुम्बई पहुंचे थे और वे पार्टी कार्यकर्ताओं से परामर्श करेंगे तथा उनके मनोबल को प्रोत्साहित करेंगे।

महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि श्री शाह की यात्रा से पार्टी काडर में विश्वास पैदा होगा। ■

हरियाणा में 60 प्लस के मिशन को पूरा करेंगे : राजनाथ सिंह

गत 31 अगस्त 2014 को पलवल (हरियाणा) में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिह ने कहा कि हम हरियाणा में 60 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर सरकार बनाएंगे। श्री सिह ने हरियाणा की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा एक समय सबसे कमजोर पार्टी कही जाती थी, लेकिन हम आप लोगों के अपार जनसमर्थन से यहां सबसे मजबूती के साथ उभरे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी राजनीतिक विश्लेषकों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के 272 प्लस का नारा देने के बाद कहा था कि हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत देते हुए इस पार्टी का कद कांग्रेस से भी ऊंचा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार- हरियाणा को नंबर वन हरियाणा बता रही है, लेकिन असल में हकीकत यह है कि हरियाणा- अपराध, भ्रष्टाचार व अन्य समस्याओं के मामले में नंबर वन बन गया है।

आज केंद्र में भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस 'नेता प्रतिपक्ष' की मान्यता के लिए बार-बार मांग उठा रही है, मगर उनकी सदन में अपेक्षित संख्या नहीं है तो उन्हें 'नेता प्रतिपक्ष' का पद कैसे दिया जा सकता है? अब उनके पास 'कद' ही नहीं है तो 'पद' कैसे दे दें। पाकिस्तान की ओर से बार-बार संघर्ष विराम के उल्लंघन के मसले पर उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने कह दिया कि यह सरकार कमजोर नहीं, बल्कि फौलादी सरकार है। लेकिन पाकिस्तान बार-बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है। श्री सिह ने कहा कि जब हमें बीएसएफ के डीजीपी ने बताया कि सीमा पर 16 बार सफेद झंडे दिखा चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तब हमने कहा कि अब सफेद झंडे नहीं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के मान-सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाएगी तो हम अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।

यदि आज कांग्रेस की सरकार होती तो जैसे महंगाई बढ़ रही थी, वैसे ही बढ़ रही होती। हमने पेट्रोल की कीमत को कम किया। अब हमारी नजर डीजल पर है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। हमने जनधन बीमा योजना की शुरुआत की। एक दिन में डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों का अकाउंट खुला। एक साल के भीतर ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिसका बचत खाता इस योजना के अंतर्गत नहीं होगा।

जनधन बीमा योजना के माध्यम से अब सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता जनता के खाते में सीधे दी जाएगी। 100 दिनों में ही हमारी सरकार के सभी मंत्रालयों ने शानदार काम किए हैं।

आज हरियाणा में किसानों, बेरोजगारों और गरीबों की समस्याएं जस की तस हैं। कांग्रेस धर्म, जाति, पंथ, मजहब के नाम पर हर बार चुनाव लड़ती रही है, लेकिन हमारी सरकार नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देती। ■

मोदी सरकार के 100 दिनों की सफलता अभूतपूर्व रही है

✍ सारस्वत पाणिग्रही

जबसे नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है तभी से वो 'मिनिमम गवर्नमेंट और मेक्सिमम गवर्नेंस' पर हर कदम पर विशेष ध्यान देते रहे हैं।

2 सितंबर को मोदी सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद में 2004 के जनादेश के 10 दिन बाद 26 मई को पद तथा गोपनीयता की शपथ ली थी। सत्तारूढ़ होने 100 दिन बाद कांग्रेस और उनके सहयोग दलों के साथ-साथ समाचार प्राप्त करने वाली मीडिया भी नरेन्द्र मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए बेहद उत्सुक रहे हैं।

ईमानदारी की बात यही है कि जब नरेन्द्र दामोदर दास मोदी 14वें प्रधान के रूप में कार्य संभाला तब 26 मई से पहले और बाद के अंतराल के बीच कोई भी स्वतंत्र टिप्पणीकार महसूस करते हैं कि इस दौरान भारत की गाथा में भारी परिवर्तन आया है। वह यूपीए की पिछली सरकार के दस-वर्षों की नीति-पंगुता निर्धारित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनके 100 दिन का काम बताता है कि वह सही दिशा में चल रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं के भार पर अपने कंधों पर उठाया है। प्रधानमंत्री उनकी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। पिछले 100 दिनों में, देश नीति-पंगुता युग से बाहर निकल कर नीति प्राथमिकताओं के युग में पहुंच गया है। अपने पद ग्रहण करने के 100 दिन बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक भारत के विकास का रोड़मैप तैयार कर लिया है।

> ***जब से नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से उनका ध्यान हर कदम पर 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' पर रहा है। मोदी सरकार के गवर्नेंस में 'सबका साथ, सबका विकास' ने नागरिकों के मन में भरोसे का भाव भर दिया है। नि:संदेह, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रोएक्टिव रवैया अपनाया है। मंत्रालयों की कार्य-संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव सामने आ गया है। ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही की एक नई भावना सभी मंत्रालयों में आने लगी है। मंत्रालयों और ब्यूरोक्रेटों में एक जबर्दस्त दबाव पड़ा है कि वे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुट जाएं।***

जब से नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से उनका ध्यान हर कदम पर 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' पर रहा है। मोदी सरकार के गवर्नेंस में 'सबका साथ, सबका विकास' ने नागरिकों के मन में भरोसे का भाव भर दिया है। नि:संदेह, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रोएक्टिव रवैया अपनाया है। मंत्रालयों की कार्य-संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव सामने आ गया है। ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही की एक नई भावना सभी मंत्रालयों में आने लगी है। मंत्रालयों और ब्यूरोक्रेटों में एक जबर्दस्त दबाव पड़ा है कि वे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुट जाएं।

100 दिनों तक सत्तारूढ़ रहने के बाद निम्नलिखित 10 बातों पर उपलब्धि प्राप्त की है:

1. काला धन देश में वापस लाना

सत्ता संभालते ही मोदी सरकार का पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन था ताकि टैक्स हैवन में जमा अवैध धन का पता लगाया जाए। एसआईटी ने पहले ही व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली है जिसमें इंस्टीट्यूशनल ढांचा बनाया गया है जिससे भारत काले धन के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकेगा।

2. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना

मुद्रास्फीति रोकने के लिए मोदी सरकार ने राज्यों से कहा कि वे फल-सब्जियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) की सूची से हटा दें। इस निर्णय से किसानों को बिचौलियों से सुरक्षा मिलेगी और जमा खोरी रोकने में सफल हो सकेंगे। इससे मुद्रास्फीति रोकने में मदद मिलेगी।

मुद्रास्फीति रोकने से आर्थिक विकास निरंतर बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। यह बात महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय अर्थव्यवस्था ढाई वर्षों में विकास के सर्वोत्तम आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं। अप्रैल-जून की तिमाही में जीडीपी वृद्धि पिछले नौ महीनों में सबसे अधिक रही। यह इस बात का संकेत है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता जा रहा है।

3. जन-धन योजना

मोदी सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' की शुरूआत की है। इस महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों के बैंक खाते खोल कर व्यापक रूप से वित्तीय

अर्थव्यवस्था में शामिल करना है, जो अभी तक इस प्रक्रिया से बाहर रहे हैं। उद्घाटन दिवस के दिन इस योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ खाते खुलने का रिकार्ड बना है।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

केन्द्रीय बजट में प्रमुख बिंदु इंफ्रास्ट्रक्चर था। यह वह क्षेत्र रहा है जिस पर पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार सदा उपेक्षा करती रही है। सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (सेज़) को पुन: जीवित कर, तथा सार्वजनिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडलों को स्ट्रीम लाइन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया है। महत्वाकांक्षी डायमंड चतुर्भुजीय रेल नेटवर्क को देशभर के प्रमुख मैट्रो से जोड़ने का काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी '100 स्मार्ट नगरों की परियोजना के जमीनी कार्यों को भी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार ने श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूरल-अर्बन मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरूआत की है। सरकार बोर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को दृढ़ एवं आधुनिक बनाने का काम भी कर रही है।

5. जीओएम, ईजीओएम की समाप्ति

प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के समूहों (जीओएम) और एम्पावर्ड ग्रुप आफ मिनिस्टर्स (इजीओएम) को समाप्त कर दिया है जिसे यूपीए के शासनकाल में बनाया गया था। इससे मंत्रालयों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है और इस प्रणाली से अधिक जवाबदेही का रास्ता खुल गया है।

6. ब्यूरोक्रेसी का सरलीकरण

प्रशासन लोगों के पास अधिक निकट आ सके और सुनिश्चित किया जाए कि गवर्नेंस लालफीता शाही की शिकंजे में न फंसे, इसके लिए मोदी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को सरल किया है। जिसमें पारदर्शिता पर अधिक जोर दिया है। सरकार ने अखिल भारतीय (आचार) नियमावली, 1968 को संशोधित किया है। संशोधित गाइडलाइंस जनादेश का कहना है कि ब्यूरोक्रेटों को राजनैतिक निष्पक्षता, जल्द निर्णय लेना और केवल मेरिट के आधार पर सिफारिशें करनी चाहिए तथा लिए गए निर्णयों को एकमात्र सार्वजनिक हित में लिया जाना चाहिए।

7. योजना आयोग को भंग करना

नरेन्द्र मोदी सरकार ने 64 वर्षीय पुराने योजना आयोग को भंग कर दिया है। 1950 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने पूर्व सोवियत यूनियन की लाइन पर योजना आयोग स्थापित किया था जिसका उद्देश्य भारत की पंचवर्षीय योजना बनाना था। परन्तु, कांग्रेस शासन के 60 वर्षों में अधिकांशत: इसका उपयोग इस बड़ी पुरानी पार्टी के वृद्धों को बिठाने के रूप में ही किया गया। उन्होंने कांग्रेस और इसके प्रधानमंत्रियों की चापलूसी के अलावा कुछ नहीं किया। नरेन्द्र मोदी योजना के स्थान पर एक नई संस्था बनाने के काम में जुटी है जिसमें भारत की आवश्यकताओं को आज की बदलती वैश्विक आर्थिक दृश्यावली को देखते हुए इसका निर्माण किया जाए।

8. न्यायिक नियुक्तियों का पुनर्निर्माण

एक नवीन उपाय को लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराया है। इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कालेजियम प्रणाली की नियुक्तियों को निरस्त किया गया है तथा जजों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय संस्था का निर्माण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ-जस्टिस एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। इनके अलावा न्यायपालिक में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज रहेंगे। आयोग के अन्य सदस्यों में कानून मंत्री और दो प्रमुख शख्सियतें भी रहेंगी।

9. प्राचीन कानूनों को समाप्त करना

नरेन्द्र मोदी और अधिक समय काम करके प्राचीन नियमों और कानूनों को कानूनी पुस्तकों से हटाने में लगी है। इनमें से अधिकांशत: कानून ब्रिटिश के औपनिवेशिक शासन में शुरू किए गए थे और जो आज भी चला रहे हैं। ये व्यर्थ के कानूनों का आज के समय कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ये वह निरर्थक कानून है जिनसे गवर्नेंस में बाधा पड़ती है और भ्रम पैदा होता है। यह केवल कानूनी प्रक्रिया को जटिल बनाती है और प्रणाली में एक बाधा खड़ी कर देती है।

10. द्विपक्षीय कूटनीति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सार्क कूटनीति सचमुच बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए वातावरण बनाने का एक साहसी कदम रहा है। इन राष्ट्रों को जिन समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसे नरेन्द्र मोदी ने आपसी सहयोग की वृद्धि का समान एजेण्डा बना दिया है। नेपाल और भूटान की अपनी यात्रा के दौरान नरेन्द्र मोदी ने विदेशी नीति के रूप में कहीं बड़ी हिंदू विरासत का उपयोग किया। जब भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल वासित ने काश्मीरी अलगाववादियों से बात की, तब विदेश मंत्रालय से नहीं का स्पष्ट कथन कहने पर भी नरेन्द्र मोदी सरकार ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया।

भारत के इतिहास में पहली बार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस पर जो दिया कि कश्मीरी अलगाववादियों तथा विभिन्न लॉबिस्टों द्वारा उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। नरेंद्र मोदी द्वारा जापान की वर्तमान यात्रा ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारत-जापान स्ट्रेटेजिक तथा ग्लोबल सहयोग से एशिया में शक्ति-संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है।

किसी सरकार के शासन को समझने के लिए 100 दिन की अवधि बहुत कम होती है। आइए, हम इंतजार करें और धैर्यपूर्वक देखें कि भारत के वास्तविक विकास की गाथा आने वाले समय में विकास-आधार की गाथा बनेगी। ■

पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितम्बर पर विशेष

एक मानव तनधारी देवदूत

के आर मल्कानी

पंडितजी सामान्य प्रकार के नेता नहीं थे। अधिकांश नेता देखने में 'हीरो' जैसे जान पड़ते हैं, मनीषियों जैसी बातें करते हैं तथा स्वयं को मानव- जाति से ऊपर का प्राणी समझते हैं। दीनदयालजी में ऐसी कोई बात नहीं थी। वे देखने-सुनने में बिलकुल सामान्य व्यक्ति जान पड़ते थे परन्तु वे इस अर्थ में बड़े असाधारण थे कि उनका जीवन बड़ा सादा था, विचार बड़े स्पष्ट थे, मनुष्यों एवं समस्याओं की उन्हें बड़ी सही पहचान थी और उनका चरित्र बड़ा ऊंचा था। वस्तुतरू वे एक ब्रह्म संन्यासी थे, जो संसार में रहते हुए भी उससे परे रहता है। जबकि अधिकांश नेताओं के सम्बन्ध में यह बात लागू होती है कि ज्यों-ज्यों उनके बारे में आपकी जानकारी बढ़ती जाती है, उनके प्रति आपका सम्मान घटता जाता है परन्तु पंडितजी इसके ठीक विपरीत थे। ज्यों-ज्यों आप उन्हंह अधिक जानने लगते, उनके प्रति आपका सम्मान बढ़ता जाता।

यह कहने में मुझे संकोच नहीं कि जब मैं सन् 1948 में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ पर लगे प्रतिबन्ध के दिनों में उनसे पहली बार मिला तो मैं उनसे विशेष प्रभावित नहीं हुआ था परन्तु मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुस्त युवक स्वयंसेवक उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे ठीक थे। मैं वर्षो तक उन्हें 'दीनदयाल' ही कहकर पुकारता रहा परन्तु ज्यों-ज्यों मैं उनके निकट आता गया, मैं भी उन्हें अनायास ही 'पंडितजी' कहने लगा। यह उस व्यक्ति तथा उसके नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता थी।

पंडितजी तथा 'आर्गेनाइजर'

लगभग पन्द्रह वर्ष पहले हमने उनसे 'ऑर्गेनाइजर' के लिए एक साप्ताहिक स्तम्भ लिखने का आग्रह किया। वे मान गये परन्तु अत्यधिक व्यस्तता के कारण वे उसे कभी-कभी लिखकर नहीं दे पाते थे। कुछ वर्षो के पश्चात् उन्होंने जगदीशजी से कहा कि जब मैं दिल्ली आता हूं तो मुझे डर लगा रहता है कि 'ऑर्गेनाइजर' मुझ से शिकायत करेगा कि मैंने अमुक-अमुक सप्ताह में अपना स्तम्भ नहीं लिखा। इसके पश्चात् मैंने उनसे लेख के सम्बन्ध में कहना बन्द कर दिया। जब उन्हें समय मिलता तो वे लिखकर भेज देते थे। यदि मैंने उनसे कहना बन्द न किया होता तो कदाचित् आज देश उनके और भी विचारों से लाभ उठा पाता।

बंगलौर के स्वर्गीय प्रो एम. ए. वेंकटराव ने एक बार उन्हें सुझाव दिया कि जनसंघ के पास अपना एक समाचार-पत्र होना चाहिए। पंडितजी ने उत्तर दिया, ''जब ऑर्गेनाइजर से काम चल जाता है तो इसकी क्या आवश्यकता है।'' जब मैंने यह सुना तो सोचा कि मेरे उत्तरदायित्व का बोझ अब बढ़ गया है। एक बार मैंने पंडितजी से पूछा कि कुछ विशेष मामलों पर क्या मुझे नरम .ष्टिकोण अपनाना चाहिए। पंडितजी नेउत्तर दिया, ''ऐसा क्यों? खूब कसकर तथा कड़ाई से लिखो। विरोधी दल का पत्र होने के नाते तुम सरकार के प्रति नरम दृष्टिकोण रखकर अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते।''

स्वभाव से ही विद्वान्

एक बार एक आगुंतक ने कहा कि जनसंघ में और सब तो ठीक है परन्तु वह थोड़ा प्रतिक्रियावादी है। पंडितजी मुस्कराये और बोले, ''मैं सामान्य रूप से प्रयुक्त 'प्रगतिशील' और 'प्रतिक्रियावादी' शब्दों के अर्थ तो नहीं

समझता, परन्तु इतना मैं जानता हूं कि हम अपने भाषणों में रूस की अपेक्षा अमरीका की अधिक आलोचना करते हैं।''

जब जॉन मथाई ने कर-सुधार के सम्बन्ध में अपना तीन-खंडीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तब पंडितजी ने उसे पढ़ने के लिए मुझसे उसके तीनों ही खंड ले लिये। कदाचित उन्हें पढ़ने से अधिक अन्य कोई वस्तु पसन्द नहीं थी। स्वभाव से ही वे एक अन्वेषक थे।

दिल्ली नगर-निगम के चुनाव में जनसंघ को पर्याप्त सीटों पर (80 में से 27 पर) विजय मिली थी और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका था। निगम के एक समृद्धशाली स्वतंत्र सदस्य आए और यह कहने लगे कि जनसंघ भाग-दौड़ करके बुझ स्वतंत्र सदस्यों को अपने दल में मिला ले और बहुमत बनाने का प्रयास करें। पंडित जी ने तनिक भी उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने उत्तर दिया, ''भाग-दौड़ करने के लिये हमारे पास एक कार भी तो नहीं है। वे ही ऐसा कर सकते हैं जिनके पास कार हो (उनका तात्पर्य उन्हीं सदस्य महोदय से था)। ''ऐसा कहकर उन्होंने स्वतंत्र सदस्यों की इच्छा पर ही यह छोड़ दिया कि वे जनसंघ में आना चाहें तो आवें।''

एक दिन की बात है कि पंडितजी, बाला साहब देवरस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महामंत्री) तथा कुछ अन्य लोग चाय पी रहे थे। खाद्य सामग्री आते देखकर उन्होंने मेजबान से कहा, ''इसमें बाला साहब के लिए तो कुछ भी नहीं है।'' (बाला साहब निम्न रक्तचाप के कारण कभी-कभी मांसाहारी भोजन करते थे)। यद्यपि पंडितजी स्वयं शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन उन्हें दूसरों की सुविधाओं का भी बड़ा ध्यान रहता था। वे तो प्याज भी नहीं खाते थे परन्तु इसको लेकर वे कोई आडम्बर नहीं करते थे। यदि उनकी तश्तरी में प्याज के टुकड़े पड़ भी जाते तो वे उन्हें निकाल देते और शेष वस्तु खाने लगते।

शांत एवं विचारशील

लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व जब गो-हत्या के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे हत्या किए गये पशुओं की खालों से बने जूते कभी नहीं पहनेंगे। उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि वे केवल ऐसे पशुओं की खालों से बने चप्पल और जूते खरीदेंगे, जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई होगी। यदि उन्हें ऐसे जूते न मिलते तो वे कपड़े के जूते खरीद लेते।

जब अरब-इजरायल का युद्ध प्रारम्भ हुआ और लगभग सभी लोग इजरायल के पक्षपाती हो गये, तब पंडितजी ने लोगों को चेतावनी दी, ''हम लोगों को आख मूंदकर केवल इसलिए इजरायल का पक्षपाती नहीं हो जाना चाहिए कि कांग्रेस आख मूंदकर अरबों का समर्थन कर रही है। हमें संसार को यों नहीं देखना चाहिए कि इसमें देवता और दानव रहते हैं। वास्तव में, हमें प्रत्येक मामले की लाभ-हानि को ध्यान में रखकर उस पर अपना मत निश्चित करना चाहिए।''

डा. जाकिर हुसैन एवं चह्वाण के सम्बन्ध में

जुलाई, 1968 को 'ऑर्गेनाइजर' के प्रकाशन को 20 वर्ष पूरे होने पर हमने इसके उपलक्ष्य में एक छोटा-सा समारोह आयोजित किया और किसी मुस्य अतिथि की खोज करने लगे। मैंने पंडितजी से पूछा कि क्या वे कोई नाम बता सकते हैं। उन्होंने एक क्षण का भी विलम्ब किये बिना उत्तर दिया, ''डा. जाकिर हुसैन को क्यों नहीं बुला लेते?'' मैं मुस्करा पड़ा। केवल दो मास पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव में हमने उनके विरुद्ध प्रचार किया था परन्तु पंडितजी अड़े रहे, ''हाँ, हां, क्यों नहीं?'' यह दूसरी बात है कि हमने अंत में यह निर्णय किया कि कोई भी मुख्य अतिथि न बुलाया जाए।

हरियाणा, पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब में जब तीन दिन के अन्दर ही गैर-कांग्रेसी सरकारों का पतन कर दिया गया तो हमने 'ऑर्गेनाइजर' में एक व्यंग्य चित्र छापा जिसमें चह्वाण को सांडरूपी लोकतंत्र की हत्या करते हुए दिखाया गया था। अनेक व्यक्तियों के विचार में ऐसा करना आवश्यकता से अधिक था। पंडितजी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ''व्यंग्य चित्र में भी गाय की हत्या दिखाना बड़ा वीभत्स है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक स्थिति इतनी डांवाडोल है कि आप यह नहीं जानते कि आपको किसके साथ बैठना होगा।''

खेद एवं सन्तोष

मैं बीस वर्षो से उन्हें जानता था और मैंने उन्हें कभी क्रोध में ऊंची आवाज से बोलते नहीं देखा। भारतीय राजनीति में बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए उन्होंने अधिक से अधिक यह कहा कि 'बड़ा बदमाश है' और वह भी क्रोध में नहीं, बल्कि आश्चर्य प्रकट करते हुए कि मनुष्य इतना बुरा हो सकता है।

ऐसे थे पंडितजी, एक मानव तनधारी देवता। यह खेद हमें जीवन भर बना रहेगा कि वे हमें अपने जीवन के चरमोत्कर्ष के समय छोड़कर चले गए। हमें केवल यह सोचकर सन्तोष करना पड़ेगा कि यही बड़े भाग्य की बात थी कि वे हमारे बीच इतने दिनों तक रहे और उनका आदर्श सदा ही हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहेगा। ■

(राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्र 'ऑर्गेनाइजर' के संपादक रहे स्व. के. आर. मल्कानी का यह लेख दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'दीनदयालजी' से साभार)

भाजपा समितियों का गठन

मार्गदर्शक मण्डल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी की गतिविधियों के मार्गदर्शन हेतु निम्न वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शक मण्डल के नाते नियुक्ति की है:-

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री नरेन्द्र भाई मोदी
श्री लालकृष्ण आडवानी
डॉ. मुरली मनोहर जोशी
श्री राजनाथ सिंह

केन्द्रीय संसदीय बोर्ड

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी की केन्द्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया है। जिसके सदस्य निम्न प्रकार रहेंगे:-

1. श्री अमित शाह (अध्यक्ष)
2. श्री नरेन्द्र भाई मोदी
3. श्री राजनाथ सिंह
4. श्री अरुण जेटली
5. श्रीमती सुषमा स्वराज
6. श्री एम. वेंकैया नायडू
7. श्री नितिन गडकरी
8. श्री अनंत कुमार
9. श्री थावरचंद गेहलोत
10. श्री शिवराज सिंह चौहान
11. श्री जगत प्रकाश नड्डा
12. श्री रामलाल

केन्द्रीय चुनाव समिति

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति का गठन किया है। जिसके सदस्य निम्न प्रकार रहेंगे:-

1. श्री अमित शाह (अध्यक्ष)
2. श्री नरेन्द्र भाई मोदी
3. श्री राजनाथ सिंह
4. श्री अरुण जेटली
5. श्रीमती सुषमा स्वराज
6. श्री एम. वेंकैया नायडू
7. श्री नितिन गडकरी
8. श्री अनंत कुमार
9. श्री थावरचंद गेहलोत
10. श्री शिवराज सिंह चौहान
11. श्री जगत प्रकाश नड्डा
12. श्री रामलाल
13. श्री जुएल ओराम
14. श्री शाहनवाज हुसैन
15. श्रीमती विजया रहाटकर (पदेन)

बिरेन्द्र सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह की उपस्थिति में हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य चौधरी बिरेन्द्र सिंह ने कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, श्री जे.पी. नड्डा, भाजपा हरियाणा के प्रदेश सह-प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव डॉ. अनिल जैन व भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, श्री श्रीकांत शर्मा भी उपस्थित थे। ■

कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने हरियाणा प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव हेतु श्री कैलाश विजयवर्गीय (मध्य प्रदेश) को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। ■